असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **01 मार्च, 2016 ई०**

---------- **मंगलवार,तिथि----------**

द्वितीय सत्र **11 फाल्गुन,1937(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री नंद किशोर यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिन पर बधाई देते हैं, मुबारक हो।

अध्यक्ष : आप सब लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लें, आप सबों की भावना को मैंने समझा है.....

श्री प्रेम कुमार : माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिन पर कोटि-कोटि बधाई ।

अध्यक्ष : और हमलोगों को भी ज्ञात हुआ है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सभा नेता भी हैं, उनका आज जन्म दिन है, इसलिए हम सदन की तरफ से और सदन के सारे सदस्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्म दिन की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, एक मिनट महोदय । किसानों का मुद्दा है, राज्य में सरकार के द्वारा धान की अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य तय किया गया था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है और बोनस की भी सरकार ने घोषणा नहीं की है । माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिन है, हम आग्रह करेंगे कि आप घोषणा कर दीजिए । किसानों के लिए जो बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है और साथ-ही-साथ रबी फसल का सरकार ने जो डीजल सबसिडी दिया है, वह राशि भी किसानों तक नहीं पहुंच पायी है । हमारा आग्रह होगा कि सरकार संज्ञान ले और जीरो आवर में इसपर सरकार का जबाब हो ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर-काल ।

तारांकित प्रश्न ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-150 (श्री रामविशुन सिंह)</u>

प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी : महोदय, खंड-1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त सूचना के अनुसार भवन प्रमंडल द्वारा विश्वविद्यालय के नये परिसर में छात्रवास का निर्माण कराया गया है, परंतु उसे हस्तगत नहीं कराया गया है । छात्रावास

भवन निर्माण विभाग से हस्तगत होने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जायेगा । तत्पश्चात् छात्रावास का आवंटन किया जा सकेगा ।

श्री रामविशुन सिंह : तो क्या महोदय, अभी तक इसी प्रक्रिया में छात्रावास चलेगा ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, इसको देखवा लेते हैं, भवन निर्माण विभाग से जल्द-से-जल्द इसको लेकर करा देते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0:151 (श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, खंड-1- अस्वीकारात्मक है ।

मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत 2459+1 मदरसों की सूची में यह मदरसा सन्निहित नहीं है ।

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1987 में ही इस मदरसा का सैंक्सन हुआ था और आज के दिन वह एक प्राइवेट घर में चल रहा है । वहां पर बड़ी असुविधा हो रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए हम मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इसपर विचार करें ।

श्री अशोक चौधरी : महोदय, इसपर विचार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-152 (श्री श्याम रजक)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, (1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

कुल 68 लाख पेंशनधारियों में से लगभग 62 लाख पेंशनधारियों का डाटा बेस तैयार है, जिसमें से दिनांक 26.02.2016 तक 19 लाख 43 हजार 647 पेंशनधारियों का बैंक खाता संख्या अपलोड किया जा चुका है ।

(3) शेष लाभुकों का खाता खुलवाने एवं उनका खाता संख्या अपलोड करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसके लिए जिलों को निदेशित किया जा चुका है और इसका सतत् अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब दिया है लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रील से खातों के माध्यम से ही लोगों को पेंशन मिलेगा । जहां तक माननीय मंत्री जी का कहना है कि 19 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा बेस तैयार है तो मेरा यह कहना है कि जब 31 मार्च तक अगर 62 लाख लोगों का खाता नहीं बनेगा तो क्या वे इससे वंचित रह जायेंगे ? उनको तो पेंशन नहीं मिल पायेगा तो मेरा यह कहना था कि यह सरकार निर्णय ले कि कैम्प लगाकर, शिविर

लगाकर लोगों का खाता खुलवा दिया जाय और 31 मार्च तक लोगों का पूरा हो जाय ताकि जो पेंशनधारी हैं, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी से कहना चाहती हूँ कि खाता खुलवाने में आधार संख्या बहुतों का नहीं बना है और बहुतों का इपिक नम्बर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो विलम्ब तो हुआ ही है लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, विभाग प्रतिबद्ध है और अप्रील माह से हमलोग चरणबद्ध तरीके से खाते में ही पैसा डालेंगे ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, जब खाता ही नहीं रहेगा, खाता ही नहीं खुला है तो खाता में पैसा जायेगा कैसे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, माननीय सदस्य जो कह रहे है और सरकार का जो निर्णय है कि 1 अप्रील से खाते में जायेगा, तो इनका कहना है कि 50 लाख लाभुक हैं, जिसमें से 10 लाख लाभुक का ही खाता खुल पाया है । आपने भी स्वीकार किया है कि किन्हीं का इपिक नहीं है, जिसके कारण दिक्कत हो गयी तो सीधी बात है कि आप एक अभियान चलाकर जो भी इसके लिए एनटाइटिल हैं या लाभुक हैं, उनका खाता खुलवा दीजिए ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : जी, मैं एक अभियान चलाकर खोलवा दूंगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–153, श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1– वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत दिनांक 19.01.2016 को 732 विद्यालयों में खाद्यान्न के अभाव में मध्याहन भोजन बंद था । उक्त विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्त्ति करा दी गयी है और वहां मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हो गयी है ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली,2013 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति नियमानुसार मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है ।

इनका अनुश्रवण आई0भी0आर0एस0 के माध्यम से किया जाता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के बंद रहने की सूचना प्राप्त होने पर उसे पुनः प्रारम्भ कराने की दिशा में कार्रवाई की जाती है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिर्फ कटिहार का नहीं, पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है । केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका संकल्प भी है कि कल के बिहार को सरकारी विद्यालय से जोड़कर शिक्षित कर उसे पौष्टिक आहार देकर एक

स्वस्थ नागरिक और शिक्षित नागरिक बनाकर वे राज्य की सेवा कर सकें, ये मूल तत्व हैं इस सारे कार्यक्रम का ।

अध्यक्ष : प्रश्न क्या है ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : मैं प्रश्न पर आता हूँ महोदय और इसके लिए एक मोनिटरिंग सिस्टम बनी हुई है लेकिन कहीं-न-कहीं वह लैप्सेज है, ये 700-800 विद्यालय का एक साथ एम0डी0एम0 बंद हो जाता है और वह तुरंत प्रारंभ नहीं हो पा रहा है और जो पौष्टिक आहार का मीनू तय किया गया है सरकार की ओर से, वह विधिवत् मीनू, वह पौष्टिक आहार युक्त नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए सरकार को विशेष रूप से एक अभियान चलाकर इस कार्य को करना चाहिए, यह पूरे सदन की चिंता है । कटिहार एक उदाहरण हमने दिया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह परिस्थिति नहीं आये, 700-800 विद्यालय में मध्याह्न भोजन की आपूर्त्ति एक साथ बंद हो जाय, इसके लिए सरकार कौन-सा ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे कि इस तरह की शिकायतें शून्य हों और मीनू के अनुसार छात्रों को मध्याह्न भोजन मिले, इसके लिए सरकार किस तरह की मोनेटरिंग कर रही है, यह हम जानना चाह रहे हैं ।

श्री अशोक चौधरी : महोदय, एफ0सी0आई0 से मध्याह्न भोजन की आपूर्त्ति होती है, कहीं-कहीं पर्टिकुलर डे को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है जिले में तो हमलोग आई0भी0आर0एस0सिस्टम से मोनेटरिंग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि तुरंत उसकी त्रुटि दूर हो, कोई पर्टिकुलर एक स्कूल की जानकारी हो या किसी विद्यालय के बारे में अगर माननीय सदस्य की चिन्ता हो, उसके लिए अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो उसकी हम जांच कराकर दोषी जो लोग होंगे, उसपर कार्रवाई करेंगे लेकिन यह पूरा फुलप्रुफ आइडिया सिस्टम है और बिहार के इस आइडिया सिस्टम को भारत सरकार एडोप्ट करने जा रही है तो यह निश्चित रूप से यह जो हमारा सिस्टम, फुलप्रुफ आइडिया सिस्टम जिससे हम मध्याह्न भोजन मोनिटर करते हैं, यह पूरे देश में एकलौता है और दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए अगर माननीय सदस्य का किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में चिंता हो, अगर बतायेंगे तो उसकी हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन से बच्चों की उपस्थिति भी जुड़ी हुई है क्योंकि सरकारी विद्यालय में साधारणतः समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे पठन-पाठन हेतु जाते हैं और मध्याह्न भोजन भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रारंभिक अवस्था में, बाद में उससे शैक्षणिक मामला जुड़ता है लेकिन मध्याह्न भोजन अगर बंद होता है तो आप पायेंगे माननीय मंत्री जी कि स्कूल में धीरे-धीरे बच्चों की उपस्थिति भी घटती जाती है, जिससे बच्चों के पठन-पाठन पर भी प्रभाव पड़ता है न कि उनके

आहार पर बल्कि उनके पठन-पाठन पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण है और यह पूरे सदन की चिंता है, यह सिर्फ कटिहार की चिंता नहीं है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में नहीं हो, सरकार इसको आश्वस्त करे ।

टर्न-2/शंभु/01.03.16/

तारांकित प्रश्न सं0-153 का पूरक

श्री प्रेम कुमार : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, बहुत स्पेशफिक इन्होंने कहा है 732 प्राथमिक और मध्य विद्यालय कटिहार में-जहां मध्याह्न भोजन बंद है और मीनू के अनुसार पहले दिया नहीं जा रहा था तो माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि कब से बंद था, किसी परिस्थिति में बंद था और कब से चालू हुआ है और विशेषकर बतायें कि क्या उसकी जॉच करायी गयी है आपके स्तर पर और जॉच यदि हुआ है तो क्या उसका फलाफल आया है ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, हमने कहा कि 19/1/2016 को 732 विद्यालयों में खाद्यान्न के अभाव में मयाह्न भोजन बंद था। उक्त विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्ति करा दी गयी है और वहां मध्याह्न भोजन योजना आरंभ हो गयी है। जब एफ0सी0आइ0 से लौजिस्टिक कभी-कभी दिक्कत होता है, लौजिस्टिक जब उठाना होता है एफ0सी0आइ0 से तो समय पर खाद्यान्न नहीं उठ पाता है तो कभी-कभी दिक्कत होती है। लेकिन भविष्य में इन समस्याओं के प्रति भी सरकार काफी सचेत है। मध्याह्न भोजन पूरे विद्यालयों मे सुचारू रूप से चले। इसके लिए सरकार की भी चिंता है। इसको हम कैसे सशक्त रूप से, मजबूत रूप से चलाये, इसपर सरकार विचार कर रही है। बजट सेशन के बाद इसपर.....

श्री प्रेम कुमार : अघ्यक्ष जी, मीनू के बारे में माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या-क्या मीनू है और क्या सही तरीके से क्वालिटी के साथ दिया जा रहा है कि नहीं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : क्या सरकार रेडी फूड दूसरे स्टेट की भांति क्या देने पर विचार रखती है ?

श्री अशोक चौधरी : अभी सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न सं0-154/श्री आबीर्दुर रहमान

श्री अशोक चौधरी : 1- वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात क्रमशः 90/1 एवं 53/1 है।

2-अररिया जिलान्तर्गत 305 माध्यमिक एवं 18 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। चतुर्थ चरण अन्तर्गत शेष रिक्ति के विरूद्ध नियोजन की कार्रवाई प्रक्रिया अन्तर्गत है।

तारांकित प्रश्न सं0-155/श्री महेश्वर प्रसाद यादव

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : राज्य में विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह 400 रूपये की राशि दी जाती है। उक्त राशि जीवन यापन हेतु नहीं बल्कि सहायता के रूप में दी जाती है। उक्त पेंशन की राशि में वृधि तत्काल विचाराधीन नहीं है।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, वृद्धा, विधवा एवं विकलांग इस राज्य के सबसे लाचार लोग हैं। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है तो बिहार में भी इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे कमजोर लोग हैं, इसलिए सरकार इसपर विचार करे।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव है सरकार इसे ग्रहण करेगी।

तारांकित प्रश्न सं0-156/श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता-अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न सं0-157/श्री समीर कुमार महासेठ

श्री अशोक चौधरी : महोदय, इसमें समय चाहिए।

तारांकित प्रश्न सं0-158/श्री (मो0) नवाज आलम

श्री संतोष कुमार निराला : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 में भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर में अनुसूचित जाति मद में 11544 छात्र-छात्राओं के बीच 69 लाख 36 हजार 4 सौ रूपया एवं अनुसूचित जनजाति मद में 54 छात्र-छात्राओं के बीच 32 हजार 4 सौ रूपया राशि का वितरण किया जा चुका है।

श्री(मो0)नवाज आलम : महोदय, हमें जो जानकारी है माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति 2013-15 से लगातार वहां तमाम छात्रों को जो अम्बेदकर कॉलेजेज हैं, उन छात्रों में हमने गहन छानबीन करने का काम किया और वहां किसी तरह की छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हुआ। महोदय, महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र आगे पीछे होने के कारण छात्रवृत्ति का फोर्म समय पर नहीं भरा जाता है जिसके कारण अनुसूचित जनजाति के लोग हमेशा उससे उपेक्षित रहते और लगातार उन लोगों के बीच

में इस तरह की भावना का हमलोगों के सदन के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि मंत्री जी ।

अध्यक्ष : नेवाज जी, आप प्रश्न के रूप में पूछिए क्योंकि प्रश्न ही पूछा जाता है, पूरक प्रश्न। आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री(मो0)नेवाज आलम : हम जानना चाहते हैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि अभी तक जो छात्रवृत्ति अगर छात्रों के बीच में वितरित की गयी है तो उसका हम चाहते हैं कि स्पष्ट उल्लेख करने का काम करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपने जो कहा है कि छात्रों या छात्राओं के बीच राशि वितरित की गयी है और माननीय सदस्य के संज्ञान में नहीं है। वह सूची उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं तो उसको उपलब्ध करा दीजिए, वे देख लेंगे।

श्री संतोष कुमार निराला : ठीक है महोदय।

श्री ललन पासवान : माननीय कल्याण मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही पूरे राज्य में उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर पूरे राज्य में 12 से 14 लाख छात्र- छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति दी जानी है। हमें जानकारी है और हमको यह भी जानकारी है कि निगरानी विभाग ने एम0एस0 राजू को जॉच के आधार पर उसपर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है। पूरे राज्य भर में अभी तक 12 से 14 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जााती है। इस बार नगण्य की स्थिति है पूरे कल्याण विभाग का, मंत्रीजी बतावें कि इस बार जो आवंटित राशि है, संपूर्ण राज्य में कितनी छात्रवृत्ति छात्रों को दी गयी है, कितना लाख छात्रों को ?

अध्यक्ष : ये सूचना आप ग्रहण कर लीजिए।

श्री संतोष कुमार निराला : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-159/श्रीमती सावित्री देवी</u>

श्री संतोष कुमार निराला : अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा मंदा पैकेट के रूप में चकाई प्रखंड चयनित था। वित्तीय वर्ष-2009-10 में 17.46 लाख रूपया, वर्ष-2010-11 में 30.13 लाख रूपया तथा वर्ष-2011-12 में 21.95 लाख रूपया व्यय कर क्रमशः कृषकों को पंपिंग सेट, सामुदायिक भवन, छात्रावास, चबुतरा आदि योजनाओं से चकाई प्रखंड के अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु अनुसूचित जनजाति उक्त योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं वन बंधु कल्याण योजना के तहत राशि विमुक्त किया जाता

है। इन योजनाओं के अन्तर्गत हाट बाजार का प्रावधान और औषधीये पौधों की खेती, बैकयार्ड, गव्य विकास, पौल्ट्री की खेती प्रशिक्षण कार्य सम्मिलित है।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बहुत इलाका है। जिसमें चकाई प्रखंड में आदिवासी समुदाय की संख्या अत्यधिक है। उन्हें आर्थिक रूप से समुन्त करने हेतु माडा योजनान्तर्गत चयनित योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया जाय एवं इसके साथ समय भी बताया जाय कि उक्त योजना का क्रियान्वयन की तिथि बताया जाय।

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वर्तमान समय में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु अनुसूचित जनजाति उक्त योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं वन बंधु कल्याण योजना के तहत राशि विमुक्त किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत हाट बाजार का परिवर्द्धन, आयुर्वेदिक पौधों की खेती, बैंक यार्ड, पौल्ट्री फोर्म.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वो सब तो आप बता चुके हैं। माननीय सदस्या का कहना है कि उनके क्षेत्र में आदिवासी बहुत इलाका है। इनके क्षेत्र का मामला है उसको देखवा लीजिएगा अलग से।

श्रीमती सावित्री देवी : माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उसका सूची उपलब्ध कराया जाय।

श्री संतोष कुमार निराला : आप मिली भी थी और जो समस्या होगी उसको दूर किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-160/श्री संजय सरावगी

श्री अशोक चौधरी : वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 05.02.14 के जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति की बैठक में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का अनुबंधन देते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-11218, दिनांक 12.08.14 के द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित किये जाने फलरूवरूप मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पदस्थापन की कार्रवाई स्थगित है। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर दरभंगा जिला में राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को विभाीय पत्रांक 266, दिनांक 14.02.16 से निदेशित कर दिया गया है।

श्री संजय सरावगी:– अध्यक्ष महोदय, दो साल से ज्यादा हो गया, 400 शि।क्ष।कों को हेडमास्टर में प्रोन्नति दी गयी है, 400 विद्यालयों के जुनियर शि।क्षकों को हेडमास्टर बनाया गया है और हेडमास्टर निकासी एवं व्ययन पदाधि।कारी भ्ाी होते हैं और 19 के 19 प्रख्ांडों में निकासी पदाधिकारी अभ्ाी डी0ई0ओ0 है, दो साल से यह अव्यवस्था चल रही है,दो साल पहले जब वहॉ की समिति ने जब निर्णय ले लिया और जिला पदाधिकारी ने भ्ाी हस्ताक्षर कर दिया, तो उसको दाबकर रख लिया गया अध्यक्ष। महोदय ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष।: आप प्रश्न पूछिये ।

श्री संजय सरावगी:– मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष। महोदय कि जब 5 फरवरी, 2014 को ही निर्णय हो गया, इनलोगों को प्रोन्नति दे दी गयी हेडमास्टर में तो किस परिस्थिति में इनलोगों को दो साल तक पदस्थापित नहीं किया गया जबकि 5 फरवरी, 2014 के तारीख में ही इनलोगों को पदस्थापित कर देना चाहिए तो किस परिस्थिति में दो साल से जब कि ज्यादा हो गया अध्यक्ष। महोदय और स्कूलों मे प्रभ्ारी प्रधानाचार्य के रुप में काम चल रहा है और वहॉ अराजकता की स्थिति है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष।:– उसके बारे में तो माननीय मंत्री जी ने बताया आपको कि सामान्य प्रश।सन विभ्ाग के किसी निदेश के तहत इसे रोका गया था ।

श्री संजय सरावगी:– क्या निदेश था और कब का निदेश था अध्यक्ष। महोदय, यह हम जानना चाहता है !

श्री अशोक चौधरी:– हम तो स्पष्ट कहें कि 5.2.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नति दे दी गयी । दिनांक 12.8.2014 को सामान्य प्रशासन विभ्ाग ने सभ्ाी प्रोन्नतियों पर यह नहीं कि केवल शि।क्षा विभ्ाग में बल्कि प्रदेश के सभ्ाी प्रोन्नतियों पर रोक लगा दी, एस0सी0/एस0टी0 का तो यह बड़ा मामला था, इसपर भ्ाी रोक लगा दी गयी,उसके बाद सामान्य प्रशासन विभ्ाग से सहमति प्राप्त कर 22.2.2016 को निदेशित कर दिया गया है कि प्रोन्नति दे दिया जाय ।

श्री संजय सरावगी:– अध्यक्ष। महोदय इसपर माननीय उच्च न्यायालय का भ्ाी आदेश हुआ,जो हेडमास्टर थे। जिनको प्रोन्नति दी गयी, वे गये उच्च न्याायालय मे और उच्च

न्यायालय का भी इसपर आदेश हुआ कि अविलंब क्यों नहीं इनलोगों को हेडमास्टर बनाया जा रहा है और अध्यक्ष। महोदय जब 14.2 को ही प्रोन्नति दी गयी और माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आठवें महीने में रोक लगी,तो सात महीना यह फाइल कहॉ थी अध्यक्ष। महोदय, माननीय मंत्री जी जरा बतावें ।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि दिनांक 22.2. को ही निदेश दे दिया गया है।

श्री संजय सरावगी:- महोदय, हमारा यह कहना है कि यह इतना गंभीर विषय है,हमलोग इसको जानते हैं,इसपर जांच करायी जाय,क्योंकि निदेशक गये थे जांच में,उन्होंने भी कहा कि किस परिस्थिति में यह नहीं किया गया, इसलिए अध्यक्ष महोदय बेजाप्ते इसकी जांच करायी जाय, दो साल तक यह किस परिस्थिति में यह लटका रहा और सब जगह काम चलाऊ व्यवस्था रखी गयी थी, तो निश्चित रुप से इसकी जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष।:- ठीक है ।

श्री संजय सरावगी:- अध्यक्ष। महोदय, यह सुनिश्चित करा दिया जाय कि इनलोगों को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा, ये केवल समय बता दें ?

श्री अशोक चौधरी:- एक सप्ताह के अंदर ।

श्री सत्यदेव सिंह:- अध्यक्ष। महोदय, एक प्रखंड में वास्तविक में एक हेडमास्टर है और उसके अंदर में 40, 45 मिडिल स्कूल है जो डिसकंटिन्यू है और आदेश हुआ था कि सिनियर लोगों को बनाया जाय लेकिन इसके लिए जिम्मेवार डी0ई0ओ0 लोग है, ये डी0ई0ओ0 लोग पॉकेट को गर्म करने को ले करके बहाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी डी0ई0ओ0 लोगों को निदेशित करें ।

अध्यक्ष।:- ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 161 (मा0सदस्य श्रीमती सावित्री देवी)</u>

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है, जहॉ पूर्व से कोई डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है ।

जमुई जिला में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर, जमुई में खोलने का निर्णय राज्य सरकार के पत्रांक-12/डायट-05/2012-45 दिनांक-22.1.2016 द्वारा लिया जा चुका है ।

सम्प्रति चकाई विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री सत्यदेव सिंह:- अध्यक्ष। महोदय यदि जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नही है और अगर वहॉ जमीन उपलब्ध करा दिया जायेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी वहॉ खुलवा देंगे ।

अध्यक्ष:- आप माननीय सदस्य कम से कम प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या का तो इंतजार कर लीजिये ।

श्रीमती सावित्री देवी:- अध्यक्ष। महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र आर्थिक रुप से सबसे पिछड़ा क्षेत्र जहॉ दलित, महादलित, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की संख्या अत्यधिक है, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है । अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि चकाई में एक उच्च शिक्षण संस्थान सह बी0एड कॉलेज खोला जाय और इसका निर्धारित एक समय सीमा बतावें ।

अध्यक्ष:- एक तो आपने खोला है न, आप बता दीजिये ।

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, गिद्धौर इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं है, इनका पार्टिकुलर है,अपने विधान सभा में खोज रही है । महोदय, अनुमंडल स्तर पर प्रॉयरिटी खोलने का चिन्हित किया गया है, जहॉ नहीं है कोई भी डिग्री कॉलेज उस अनुमंडल में तो सरकार के द्वारा खोलना है, तो 18 अनुमंडल ऐसे है बिहार में जहॉ पर डिग्री कॉलेजेज नहीं है, 10 की प्रॉयरिटी बनी है, जिसमें 8 मे अगले वित्तीय वर्ष में काम होगा ।

श्री सत्यदेव सिंह:- अध्यक्ष। महोदय..... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- आपको चकाई के बारे में पूछना है ।

श्री सत्यदेव सिंह:- महोदय, अपने प्रखंड के बारे में पूछना है । महोदय, यह जो डिग्री कॉलेज का मामला है,वह पूरे बिहार से संबंधित हो जाता है । मैंने माननीय मंत्री जी को अपने विधान सभा के दो प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया है,इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या आप वहॉ खुलवा देंगे डिग्री कॉलेज ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य इसके लिए तो अलग से न पूछियेगा या लिखकर दीजियेगा ।

श्री सत्यदेव सिंह:- जब सरकार का नीयत है कि पूरे प्रखंड में जहॉ डिग्री कॉलेज नहीं हैं, खोला जायेगा, तो हमने जमीन उपलब्ध करा दिया है,तो वहॉ खुलवा दीजिये ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव:- अध्यक्ष। महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ .....

अध्यक्ष।:- आपका प्रश्न चकाई से है !

श्री महेश्वर प्रसाद यादवरु- नहीं, लेकिन इसी प्रश्न से संबंधित एक पूरक है । मेरा प्रश्न यह है कि जिन प्रखंडों में जहॉ इन्टर कॉलेजों में काफी जमीन उपलब्ध है,उस इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज के रुप में प्रोन्नत करना चाहती है कि नहीं सरकार ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य महेश्वर बाबू, आप बैठिये । सरकार ने साफ किया है कि सरकार की योजना उन अनुमंडलों में जहॉ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, वहॉ

खोलने की है और अभी प्रश्न चकाई से रिलेटेड है, यदि आप किसी दूसरे जगह का पूछ दीजियेगा तो सरकार कहॉ से जवाब दे पायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या:-162 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय पथनौर, प्रखंड बेलसंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 10 अतिरिक्त वर्ग कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में जीर्णोद्धार मद में राशि उपलब्ध होने की स्थिति में उक्त विद्यालय के पूर्व से निर्मित तीन वर्ग कक्ष जो वर्तमान में जर्जर हो गए हैं, का जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान:- महोदय, प्रत्येक वर्ग में 40 बच्चे नामित होते हैं, इस विद्यालय मे बच्चे एवं बच्चियों की संख्या लगभग 600 से अधिक है, मात्र 6 कमरा ही स्कूल के पास है,एक कमरा प्रचार के लिए है दूसरा कमरा में एम0डी0एम0 का सामग्री रखा गया है,मात्र चार कमरा ही बच्चों के पढ़ाई के लिए है,जिससे काफी कठिनाई होती है । माननीय मंत्री जी यह नक्सल प्रभावित एरिया है,इसमें चहारदीवारी और शौचालय भी जरुरी है । इसलिए आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि ये समय सीमा बता दें कि कब तक ये करा देंगे ।

श्री अशोक चौधरी : इस विद्यालय में 10 कमरे का निर्माण तत्काल अभी तक किया गया है, पहले से 3 कमरे थे । इसके अतिरिक्त 10 कमरे का निर्माण किया गया है । और कमरे के निर्माण की आवश्यकता, जैसे ही बजट में प्रावधान होगा, आपके विद्यालय में और कमरे का निर्माण करा दिया जायेगा ।

श्रीमती सुनीता चौहान : टेन्थ का है उस विद्यायि में ।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 163 (मा0स0डा0सुनील कुमार)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

खड 2 : सरकार की नीति वैसे अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने का है, जहां पर्वू से कोई अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है ।

खंड 3 वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिले में पूर्व से नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ, नालान्दा महिला कॉलेज,बिहारशरीफ, किसान कॉलेज,सोहसराय, नालन्दा एस0यू0 कॉलेज,हिलसा एवं एस0पी0एम0उदन्तपुरी कॉलेज, बिहार शरीफ संचाालित है, जहां जिले के सभी प्रखंडों के विद्यार्थी नामाकित हो कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

खंड 4 : सम्प्रति प्रखंडवार डिग्री कॉलेज खोलने की योजना, राज्य सराकर के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

डाा0सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रहुई प्रखंड ऐसा प्रखंड है, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक जीवन शुरू किया था । पहली बार वहां से विधायक निर्वाचित हुये थे ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

डा0सुनील कुमार: आजादी के 69 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां डिग्री कॉलेज नहीं खुला । अगर डिग्री कॉलेज होता तो नालन्दा की बेटी किसी विधायक के हवस का शिकार नहीं होती । 2010 के 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कार्यक्रम में प्रखंड कार्यालय रहुई में घोषणा किये थे कि रहुई में डिग्री कॉलेज,आइ0टी0आई0 और एक खेल का मैदान बनायेंगे, जिसे आज तक पूरा नहीं किया । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते है कि क्याा वहां अविलंब डिग्री कॉलेज खोालना चाहते हैं ताकि नालन्दा की और बेटियां किसी के हवस का शिकार न बन सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय मंत्री ने आपको बता दिया कि सरकार की नीति अभी अनुमंडल में एक खोलने की है, प्रखंडस्तर पर कौलेज खोलने की नीति अभी नहीं बनी है,उन्होंने तो बता दिया ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 164 (मा0स0 श्री अशोक कुमार)

(मा0स0 अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 165 (श्री राजीव नंदन)

श्री चन्द्रिका राय : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : उत्तर अस्वीकारत्मक है । जिला परिवहन पदाधिकारी सह करारोपण पदाधिकारी, गया द्वारा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधि0,1994 अतर्गत निबंधित लदान क्षमता पर ही कर की वसूली की जाती है ।

खंड 3 : जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियिम,1994 के अन्तर्गत मालवाहकों पर निबंधित लदान क्षमता पर ही कर की वसूली की जा रही है, जो नियमानुकूल है ।

श्री राजीव नन्दन : महोदय, अधिनियम,1994 के अन्तर्गत जो कर वसूली के नियम हैं मोटर वाहन पर उसमें माल वाहक वाहन में उनके लदान क्षमता पर कर वसूली करने का नियम है । लेकिन जब कर की वसूली की जाती है तो मोटर व्हेकिल का जितना वजन होता है और उनकी लदान क्षमता दोनों को जोड़कर कर की वसूली की जाती है, यह बात इनके टैक्स टोकन में वर्णित है । यह सिर्फ गया जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है । मालवाहक के जितने भी वाहन चालक हैं या वाहन मालिक हैं, उनलोगों का दोहन हो रहा है। इसमें पूरे सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यक्ता है ।

श्रीचन्द्रिका राय : अध्यक्ष महोदय, टैक्स टोकन पर जो लिखा रहता है कि वाहन कितना माल ढो सकती है, पूरा वेट ट्रक के लोड के साथ-साथ उस पर कितना वेट लाड करना है,उसकी सीमा निर्धारित है, उससे अधिक कोई ओवर लोड करता है तो उस पर फाईन किया जाता है ।

श्री राजीव नन्दन : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सबूत है और सबूत सदन के पटल पर है । अगर सदन सहमत है तो इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सिर्फ इतना कह रहे है, इनका कहना है कि माल के वजन पर टैक्स लगना चाहिए जबकि ट्रक सहित जो तौल होता है ।

श्री चन्द्रिका राय : टैक्स टोकन पर लिखा रहता है, वाहन का भार और उस पर लोड किया हुआ सामान ।

अध्यक्ष : आपके कहने का मतलब है कि उस पर गाड़ी का वजन लिखा रहता है ।

श्री चन्द्रिका राय : गाडी का वजन और कितना वह ढो सकता है दोनों मिला कर निर्धारित सीमा तय की रहती है ।

अध्यक्ष : और टैक्स किस पर लगता है ?

श्री चन्द्रिका राय : जब ओवर लोग्डिंग रहती है ।

अध्यक्ष : टैक्स लगता किस पर है ? गाड़ी के वेट पर भी लगता है या सिर्फ माल पर टैक्स लगता है ?

श्री चन्द्रिका राय : ओवर लोडिंग की स्थिति में जो सीमा निर्धारित है, उससे ओवर लोडिंग होने पर प्रति टन के हिसाब से लगता है ।

श्री राजीव नन्दन : अध्यक्ष महोदय, यहां ओवेर लोडिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । ओवर लोडिंग का कहीं कोई बात नहीं है । यहां सीधे लिखा हुआ है कि टोटल वेट । यहां ओवर लोाडिंग की कोई बात ही नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहना यह चाहे रहे हैं ।

श्री राजीव नन्दन : यह मामला बहुत ही गंभीर है। 1994 से ही माल वाहक के लोगों का शोषण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आपके कागजात में हम देख लेते हैं । लेनिक इनका कंसर्न इतना है कि माल के वजन पर टैक्स लगना चाहिए, गाड़ी के वजन पर टैक्स नहीं लगता चाहिए । इसको आप दिखवा लीजियेगा ।

श्री चन्द्रिका राय : जी ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि प्रश्न कोी स्थगित कर दीजिये । मंत्री जी और समझ कर आ जायें, अगले सप्ताह इसका जवाब दे दें । महोदय, आप भी स्पष्ट नहीं हैं मंत्री महोदय के जवाब से । इसलिए मेरा आग्रह होगा कि प्रश्न को स्थगित कर दीजिये । मंत्री जी तैयारी करके आवे, अगले सप्ताह में इसका जवाब दें दें ।

श्री चन्द्रिका राय : क्या चीज का तैयारी करके आयें ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 166 (मा0स0 श्री सैयद अबु दोजाना)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 167 (मा0स0 श्री राम विशुन सिंह)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : उत्तर स्वीकारात्मक हैं

खंड 3 : वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पत्रांक 74 दिनांक 14.01.2016 द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु कुल 5,86,10,952/-रूपये मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है । सरकार प्राप्त प्राक्कलन की तकनीकी पहलुओं की जांच कराकर निर्णय लेगी ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, कबतक बनेगा प्रशासनिक भवन ? 24 साल विश्वविद्यालय का हो गया, अभी तक विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन नहीं बना । कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 14.01.2016 को विश्वविद्यालय से प्राक्कलन ही आया है । प्राक्कलन की तकनीकी जांच कराकर जल्दी इस पर निर्णय लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 168 (मा0स0 डा0अशोक कुमार)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाना है ।

खंड 3 : प्रश्नगत विद्यालय के चिन्हित पंचायत रहियार उत्तर एवं बंधार में पूर्व से क्रमशः अनुदानित जनता उच्च विद्यालय पटेल नगर चित्तौरा बेला (रहियार उत्तर पंचायत) स्थापित एवं संचालित है ।

अतः प्रश्नगत पंचायत माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है ।

डा0अशोक कुमार : महोदय, माननीय मंत्री ने जहो उच्च विद्यालय बताया वह उससे काफी दूर है और इसीलिए इस विद्यालय यका उत्क्रमित करना अत्यंयत आवश्यक है । इस विषय में सरकार क्या सोच रही है ।

श्री अशोक चौधरी : अभी फिलहाल जो सर ने पूछा था उसके बारे में हमारा इतना ही कहना है कि उस पंचायत में ऑल रेडी है, लेकिन उसकी दूरी कितनी है, स्पेसिफिक बतायेंगे, संभव हो सकेगा तो उसको हम कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 169 (मा0स0 श्रीमती कुन्ती देवी)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत निम्न विदयालयों में शिक्षकों का स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों की स्थिति निम्न है :-

विद्यालय का नाम	माध्यमिक		उच्च माध्यमिक	
	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
यशवंत उ0वि0,खिजरसराय -	16	16	20	5
जगदीशचन्द्र उ0वि0टेटुआ -	10	4	20	4
पुनित उ0वि0भैया बिगहा,उपथू -	10	10	12	1
गुलाबचन्द्र उ0वि0निमचक,बथानी-	10	5	12	3

प्रश्नगत विद्यालय में शेष रिक्ति के विरूद्ध नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक की कमी है स्वीकृत बल के आधार पर । वहां कार्रवाई कर रहे हैं

श्रीमती कुन्ती देवी: अघ्यक्ष महोदय,पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या होगी? स्कूल में बाऊंड्री भी नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-170

श्री अशोक चौधरी: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

राज्य के 53640 अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एन0सी0टी0ई0,नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन्हें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,बिहार,पटना द्वारा ओ0डी0एल0मोड से जुलाई,2016 से प्रशिक्षित करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

श्री संजय सरावगी: अघ्यक्ष महोदय,जो हालत है शिक्षकों का, मतलब एक लाईन हिन्दी भी जो है शिक्षक नहीं लिख पाते हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 53 हजार..

अध्यक्ष: दूसरी भाषा लिखते हैं कि नहीं?

श्री संजय सरावगी: नहीं सर, कोई भी भाषा नहीं लिखते हैं।

अध्यक्ष: आपने तो कहा कि हिन्दी नहीं लिखते हैं।

श्री संजय सरावगी: ये आये दिन अखबार में ही छपता है और प्रिंट मीडिया में भी आता है। सबलोग देखते हैं उसी तरह से हमलोग भी देखते हैं।

अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये?

श्री संजय सरावगी: माननीय मंत्री जी ने कहा कि 53640 अप्रशिक्षित हैं। जल्द ही हम उनको प्रशिक्षित करेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राज्य में कितने प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उसकी क्षमता कितनी है और 53000 शिक्षक उस क्षमता के अनुसार कबतक प्रशिक्षत हो जायेंगे?

अध्यक्ष: उन्होंने तो कहा कि एन0सी0टी0ई0 के माघ्यम से करा रहे हैं।

श्री संजय सरावगी: एन0सी0टी0ई0 के माघ्यम से ही, राज्य में जो प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता है महोदय वहीं जाकर के तो प्रशिक्षित होंगे न? इसीलिए तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कितनी क्षमता है अपने राज्य में ?

श्री अशोक चौधरी: इनका अनसर सर हम नहीं दे पायेंगे चूंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितनी संख्या है लेकिन हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि जितनी हमारी संख्या थी और जो हमारा सिस्टम था उसको हमलोगों ने अपग्रेड किया है। बहुत जगह ट्रेनिंग स्कूल हमलोग खोलने जा रहे हैं, बल्र्ड बैंक से भी हमलोगों ने बात किया है। हमलोग ट्रैनिंग स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से चिन्तित है जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको ट्रेंड करने के लिए और जुलाई 2016 से इसको हमलोग एक प्लान- वे में शुरू करने जा रहे हैं।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय,बहुत गंभीर इश्यू है और माननीय मंत्री जी की तैयारी नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो इसलिए इसको स्थगित किया जाय अध्यक्ष महोदय और अगला, जिस दिन शिक्षा विभाग का है उस दिन माननीय मंत्री जी पूर्ण तैयारी से आवें और बतावें कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर अपने छात्रों को, बच्चों को नहीं मिलेगी और जो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए अगले दिन इसको रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है, पूरा बिहार इससे चिन्तित है अगर हमारे बच्चे ही अच्छी शिक्षा नहीं पायेंगे...

अध्यक्ष: करेंगे। माननीय मंत्री जी ने आपकी बात को गंभीरता से सुना है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 171

श्री जय कुमार सिंह: महोदय,राजकीय सुशासन कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक जिले में एक राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से नालंदा जिलान्तर्गत रहुई प्रखंड के निकट ही अस्थावां प्रखंड में नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान में सत्रारंभ हो चुका है। वर्त्तमान में नालंदा जिलान्तर्गत रहुई प्रखंड में कोई भी पोलिटेकनिक संस्थान प्रस्तावित नहीं है।

डॉ0 सुनील कुमार: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून 2010 में घोषणा किया कि रहुई प्रखंड में पोलिटेकनिक कॉलेज बनाया जायेगा तो मैं आपके मायम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब प्रस्ताव नहीं था इतने ऊंचे पद पर बिहार के मुख्यमंत्री होकर और उसी प्रखंड में जहां से उन्होंने राजनीति जीवन शुरू किया, पहली बार विधायक बने वैसे लोगों को....

तारांकित प्रश्न संख्या- 172

श्री नन्द किशोर यादव: अध्यक्ष महोदय,सरकार जवाब नहीं दे रही है और ऐसे बढ़ते जायेंगे तो कैसे होगा?

अध्यक्ष: माननीय नन्द किशोर बाबू,आपके माननीय सदस्य पूर्ण रूप से संरक्षित है, आप इत्मिनान रहें।

श्री नन्दकिशोर यादव: बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो मुख्यमंत्री के घोषणा का पालन नहीं करने का कारण बतलाना चाहिए सरकार को। आखिर मुख्यमंत्री जी के घोषणा का पालन क्यों नहीं हुआ सरकार को बतलाना चाहिए महोदय अगर आप टालते जायेंगे तो काम कैसे होगा बिहार का।

श्री अशोक चौधरी: 1-वस्तु स्थिति यह है कि विद्यालय कैम्पस का चहारवारी. है परन्तु विद्यालय से सटे मैदान का चाहरदिवारी नहीं है

2-उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन कार्य में कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

3–उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है।

मो0 आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय,मध्य विद्यालय तो वहां पर है लेकिन उसके चारों तरफ जो है लोग बस गये हैं और खेती भी करते हैं ओर दूसरी तरफ यह है कि वहां मंदिर भी बना दिया गया है। स्कूल के फिल्ड में मंदिर बन गया है उससे भी काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। वहां के बच्चे को भी खेल के मैदान में खेलने में बहुत दिक्कत हो रहा है इसीलिए हम आग्रह करेंगे मंत्री महोदय से कि इस तरह के कई स्कूल हमारे यहां क्षेत्र में है वो सब का घेराबंदी जरूर करा दें। उसका अतिक्रमण भी काफी हो रहा है। यह कबतक करायेंगे हम इसका आश्वासन चाहते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या– 173

श्री नन्द किशोर यादव: अध्यक्ष महोदय,हम जानना चाहते हैं कि क्या अवधेश बाबू मंत्रिपरिषद से हट गये हैं? इसलिए कि उनका स्थान उधर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मंत्री महोदय के बैठने का जो स्थान है, शायद हटा दिये गये हैं।

अध्यक्ष : अवधेशबाबू माननीय श्री नन्द किशोर जी आश्वस्त हैं कि आप मंत्री पद से हटे नहीं है सिर्फ आपको अपने सीट पर जाने का ईशारा कर रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार सिंह: महोदय,हम अपने सी0एल0पी0 लीडर से कुछ परामर्श करने के लिए यहां पर आये हैं, इससे नन्द किशोर बाबू बड़ी चिंतित हो गये हैं।

श्री नन्द किशोर यादव: आप तो पुराने सदस्य हैं और जिनसे परामर्श लेने आये हैं वो भी और पुराने सदस्य हैं लेकिन सदन में परम्परा नहीं रही है कि अपने सीट छोड़कर परामर्श लेने का काम करें।

अध्यक्ष: आप आ जाईए। वैसे भी मंत्रीगण को सामान्य रूप से अपनी जगह पर ही बैठना चाहिए।

श्री अशोक चौधरी: 1–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है जीर्ण–शीर्ण कमरे के आलवा भी प्लस–2 विद्यालय अन्तर्गत पांच कमरे का भवन निर्मित है जिसमें पठन पाठन कार्य संचालित किया जा रहा है।

2–शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण करने की कोई विशेष योजना नहीं है।

डॉ0 रंजु गीता: अध्यक्ष महोदय,हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ आश्वस्त होना चाहती हूॅ कि क्या इस वित्तीय वर्ष में बाजपट्टी नरहा उ0वि0 जो है जिसका इतिहास गवाह है कि वहां के बच्चे जज, यू0पी0एस0सी0 और

बी0पी0एस0सी0 आदि परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण रहा करते थे, अव्वल रहा करते थे। करीब आजादी के बाद और आजादी के पहले के बीच के स्थिति में वह काफी सुदृढ़ था वहां होस्टल चलाया जाता था। वहां मघ्य वि0 और उ0 वि0 दोनों अवस्थित थी लेकिन इस अंतराल में वह पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था हो गया है और उ0 वि0 में पांच-छः कमरा या।

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

डॉ0 रंजू गीताः मैं जानना चाहती हूॅ कि इस वित्तीय वर्ष में कितने कमरे का निर्माण बाजोपट्टी,नरहा उ0 वि0 में कराने का माननीय मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं?

श्री अशोक चौधरीः प्रायोरिटी में बात करके देख लेते हैं।

डॉ0 रंजू गीताः अघ्यक्ष महोदय,अब मैं आपके माघ्यम से जानना चाहता हूॅ कि वहां कम्प्यूटर जो रखा जाता है उ0 वि0 में वहां चाहरदिवारी नहीं रहने के कारण वह भी एक वार चोरी हो गया। उसका एफ0आई0आर0 पिछले 2010-15 अवधि में जब में विधायक थी तब प्रश्न भी की थी और उसका कम्प्लेन एफ0आई0आर0 थाना में दर्ज है चाहरदिवारी की जो बात है तो उस विद्यालय के लिए कम से कम चाहरदिवारी निश्चित से होना चाहिए चूंकि ग्रामीणों के द्वारा वहां जमीन उपलब्ध कराया गया था और उस विद्यालय परिसर का दिन प्रति दिन देखते देखते अतिक्रमण होता जा है। किसानों के द्वारा उससे मुक्ति के लिए उस विद्यालय में बहुत अति आवश्यक है कि चाहरदिवारी का निर्माण कराया जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या- 174

श्री अशोक चौघ्रीः 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में चार वर्ग कक्ष उपलब्ध है जिसमें अघ्यापनका कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय माघ्यमिक शिक्षा अभियान एवं राज्य योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता के उपरांत अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

श्री सत्यदेव सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माघ्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि वहां छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और मात्र दो ही कमरा है। विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि कबतक उस विद्यालय का निर्माण हो जायेगा?

तारांकित प्रश्न संख्या- 174 का पूरक ...क्रमशः....

श्री अशोक चौधरी : महोदय, हमने कहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राशि की उपलब्धता के उपरांत अतिरिक्त कमरे का निर्माण करा लिया जायेगा । नये वित्तीय वर्ष में प्रायरिटी पर इसको रखेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 175 (श्री गिरिधारी यादव)

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य सदन में अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 176 (श्री अरूण कुमार)

श्री चन्द्रिका राय : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- तत्काल निगम के बेड़े में गाड़ियों की कमी रहने के कारण विषयांकित मार्ग पर बसों का परिचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है । वर्त्तमान में दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा-सहरसा सेवा का परिचालन किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 177 (श्री सुदामा प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित/कार्यरत प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों ; जिन्हें पूर्व के वर्ष में 71 दिनों की सामान्य अवकाश दिये जाने के कारण मात्र तीन दिनों का उपार्जित अवकाश अनुमान्य था, पर विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 645 दिनांक 31.07.87 के द्वारा वर्ष में दी जाने वाली सामान्य अवकाश को 60 दिनों का करते हुए उपार्जित अवकाश को बढ़ाकर 14 दिनों का किया गया है । ग्रीष्मावकाश एवं उपार्जित अवकाश राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को समान रूप से दिया जाता है, जिसमें संशोधन संबंधी कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 178 (श्री नारायण प्रसाद)

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य सदन में अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 179 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय गुलरिया टोल, प्रखंड घोघरडीहा में पूर्व से दो कमरा हैं जिसमें पठन-पाठन संचालित होता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक अतिरिक्त वर्ग कक्ष स्वीकृत किया गया, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।

प्राथमिक विद्यालय बगराहा, प्रखंड घोघरडीहा में दो कमरा है जिसमें पठन-पाठन संचालित होता है । अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, जिससे अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कराने में कठिनाई है ।

प्राथमिक विद्यालय, मुशहरनियॉ (दक्षिण) मल्लाह टोल, प्रखंड फुलपरास में तीन कमरे (नया विद्यालय भवन) की छत ढलाई हो चुकी है और शेष निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण करा लिया जाएगा ।

प्राथमिक विद्यालय मुशहरनियॉ (उत्तर) नवका टोला, प्रखंड फुलपरास में पूर्व से दो कमरे हैं । अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में उक्त मद में राशि स्वीकृत होने पर अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 180 (श्रीमती रंजू गीता)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्त्तमान में विभाग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना संचालित है जिसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

प्रखंड स्तर पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए वर्त्तमान में छात्रावास निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती रंजू गीता : अध्यक्ष महोदय, जवाब में तो असंतोष जाहिर हुआ । क्या इस वित्तीय वर्ष में भी सरकार विचार नहीं रखती है, प्रखंड स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर इसे बनाने के लिये ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : प्रखंड स्तर पर इस तरह की कोई योजना नहीं है और कोई विचार भी नहीं है । हमलोगों का अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास जो चलता है, उसके लिए भूमि हमलोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक सीतामढ़ी जिला में भूमि हमलोगों को उपलब्ध नहीं है । जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, उसके लिये काम फिनिशिंग पर चल रहा है, प्रखंड स्तर पर नहीं है, जिला स्तर पर ही है बनाने का ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 181 (श्री राजकिशोर सिंह)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । राज्य सरकार की नीति उन अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने की है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली विधान सभा क्षेत्र में तीन प्रखण्ड क्रमशः वैशाली, पटेढ़ी बेलसर एवं गोरौल है । वैशाली एवं पटेढ़ी बेलसर प्रखण्ड हाजीपुर अनुमंडल में ही है, जहाँ पूर्व से आर0एन0 कॉलेज, हाजीपुर, डी0सी0 कॉलेज, हाजीपुर एवं जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर संचालित है ।

विधान सभा क्षेत्रवार सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजकिशोर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जरा वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को समझें । विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी जो पर्यटक आते हैं, पूछते हैं कि आसपास में कोई डिग्री कॉलेज है, तो हमलोग निरूत्तर हो जाते हैं । हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि वैशाली की महत्ता को समझते हुये, जनतंत्र की भूमि है और वहाँ एक डिग्री कॉलेज निर्माण करने के संबंध में सरकार विचार करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वहाँ के स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय की स्थापना चाह रहे हैं या विदेशी पर्यटकों को उत्तर देने के लिए ?

श्री राजकिशोर सिंह : दोनों बात चाहते हैं । स्थानीय लोग शर्मिंदा होते हैं, वैशाली की महत्ता को समझते हुये वहाँ के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है । जब कोई पूछता है तो हमलोगों को शर्मिंदगी होती है ।

अध्यक्ष : वहाँ आवश्यकता है !

श्री राजकिशोर सिंह : जी, आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : मत्री महोदय, देख लीजिये ।

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 200 के आसपास ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है लेकिन स्टेट के जी0आर0 को कम्पलीट करने के लिए राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष से वैसे प्रखंड जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, डिस्टेंस लैंगुयेज से हमलोग उसको शुरू करने जा रहे हैं । नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी या बाकी जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो उस क्षेत्र में आते हैं, जहाँ +2 की पढ़ाई हो रही है, जहाँ +2 पहले से इफेक्टिवली चल रहा है वहाँ पर हमलोग डिस्टेंस लैंगुयेज से शुरू कर रहे हैं ।

बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की हैं । अभी फिलहाल हमलोगों का प्रखंड स्तर पर सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान

नहीं है लेकिन कुछ प्रखंड में डिग्री की पढ़ाई शुरू हो जाय, इसके लिए हमलोग डिस्टेंस मोड पर डिग्री की पढ़ाई शुरू करा रहे हैं हर प्रखंड में ।

अध्यक्ष : उसमें इनका देख लीजियेगा ।

श्री अशोक चौधरी : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 182 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के 7 निश्चय के अनुपालन में सभी जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किया जाना है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के प्रावधानानुसार अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु एक ही भूखंड में न्यूनतम 7.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है । विभागीय पत्रांक 257 दिनांक 22.01.2016 द्वारा जहानाबाद जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि उपलब्धता के लिए समाहर्त्ता, जहानाबाद से अनुरोध की गई है । विभाग में भूमि उपलब्ध या हस्तांतरित होते ही जहानाबाद जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 183 (श्री प्रमोद कुमार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ने श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह को अधिकृत किया है।

श्री अशोक चौधरी : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली-2013 के तहत प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसको विद्यालय के संचालन का दायित्व सौंपा गया है । उक्त नियमावली के नियम (15) (ज) में यह अंकित है कि शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन दिया जाएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने प्रतिवेदन अभी तक विभाग को प्राप्त हुए हैं ? शिक्षा समिति ने कितने प्रतिवेदन विभाग को भेजे हैं और उसपर कौन सी कार्रवाई की गई है ?

श्री अशोक चौधरी : स्पेसिफिक जिलावार यह डी0ई0ओ0 के पास आता है लेकिन यह बात हम स्वीकार करते हैं कि इसमें अभी त्रुटि है, इसपर अभी हमलोग वर्क आऊट कर रहे हैं कि हम कैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक कर

सकें । अध्यक्ष महोदय, हमें अभी मात्र चार महीना हुआ है, अभी एक-दो महीने का समय दिया जाय, विभाग इसमें वर्क आऊट कर रहा है कि कैसे हम अटेंडेंस को रेगुलराइज करें । सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सरकार चाहती है कि जो शिक्षकों की उपस्थिति है, उसको हमलोग रेगुलराइज करें । इसी के तहत एक नया ज्ञापन सरकार द्वारा निकाला गया है कि कोई भी शिक्षक दो दिन पूर्व ही अपना लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं । आदतन देखा गया है कि लीव एप्लीकेशन जिस दिन लीव होता है, उस दिन देते हैं । इसलिये सरकार ने एक नया आदेश निकाला है कि जो भी शिक्षक अनुपस्थित होना चाहते हैं उसके लिए दो दिन पहले आपको अनुपस्थिति के लिए लेटर देना पड़ेगा । सरकार चिन्तित है, विभाग को कुछ समय दिया जाय, इसको हमलोग ठीक से वर्क आऊट कर रहे हैं ।

टर्न-7/आजाद/01.03.2016

श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसमें त्रुटि है तो इसमें जब त्रुटि है तो आप इतना बता सकते हैं कि आपके विभाग ने इससे पहले इस संदर्भ में कौन सी कार्रवाई की है और किन-किन जिलों में कौन सी कार्रवाई की गई है ?

श्री अशोक कुमार चौधरी : राईट ऑफ एजुकेशन के बाद पूरी तरह से विद्यालय को चलाने का भार एवं अधिकार विद्यालय समिति के पास है और विद्यालय समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर विद्यालय समिति डी0ई0ओ0 को, बी0ई0ओ0 को यह लिखती है कि ये मान्य शिक्षक नहीं आ रहे हैं, नियोजित शिक्षक नहीं आ रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो उसपर कार्रवाई होती है लेकिन अभी हमारे पास पूरे बिहार का कहां से कितने जिलों ने, विद्यालयों ने पूछा है, मांगा है, उसका हमारे पास सूचना प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : शून्य-काल । श्री तारकिशोर प्रसाद ।

शून्य-काल

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, कटिहार जिला सहित पूरे राज्य में पैक्स द्वारा किसानों से धान की खरीद ठप्प है । किसान बिचौलियों के हाथ कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं । सरकार धान खरीद पर बोनस की भी घोषणा नहीं कर रही है, जिससे किसान मायूस हैं ।

अत: सरकार अविलम्ब धान की खरीद बोनस के साथ प्रारंभ करे ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, किसानों का मामला है और धान क्रय करने के मामले में सरकार की विफलता महोदय सामने आयी है । जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य था 30 लाख मे0टन, उसके 20 प्रतिशत ही हो पाये हैं । उसमें काफी शिकायत है कि जो दर तय था 1400प्रति क्विंटल लेकिन किसानों को मात्र 1200/-,1300/- रू0 दिये गये हैं और बड़ी संख्या में राज्य के किसान बिचौलियों के हाथ 900/-,1000/-रू0 में दिये हैं । इसलिए हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि पिछले साल भी लगभग ढ़ाई लाख मे0टन जो धान थे, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है । सरकार ने बोनस का एलान अभी तक नहीं किया है और रब्बी फसल पर डिजल सबसीडी जो थी, उसका भुगतान किसानों को नहीं हो रहा है । हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि किसानों के सवाल पर सरकार का महोदय जवाब हो ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत नवहट्टा एवं रोहतास प्रखण्ड के रोहतासगढ़ एवं पीपरडीह पंचायत के लगभग 70 गांवों में अभी तक इन वनवासी आदिवासी को बिजली नहीं मिलती है ।

सरकार से मांग करते हैं कि बिजली की व्यवस्था जल्द करावें ।

अध्यक्ष महोदय, पूरे पहाड़ पर पहले भी आपको बताया था, आज तक आजादी के बाद पूरे पहाड़ पर जो वनवासी आदिवासी रहते हैं, एक जगह भी बिजली नहीं है, वे दिया और लालटेन पर जीते हैं, इतनी बड़ी आबादी है लेकिन वहां पर बिजली नहीं मिलती है । इसलिए सरकार पहाड़ पर पूरे में बिजली की व्यवस्था करावे, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत स्टेट बैंक गली अमला टोला, कटिहार से उपेन्द्र कुमार सुमन नामक किसान के हाथ से दिनांक 26 फरवरी,2016 को 5 लाख रूपये की नगद राशि दो युवक एक पल्सर मोटर साईकिल पर सवार द्वारा दिन

दहाड़े लूट लिया गया, सी0सी0टी0वी0 में कैद लूटेरों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, चार-पॉच दिन बित गया और रोज कटिहार जिले के अन्दर में इस तरह की घटनायें घट रही है । 10लाख रू0 भी आज से 10 दिन पहले एक लड़का से लूटा गया था और इस तरह की घटना में वहां की पुलिस बिल्कुल अक्षम है, इसपर ध्यान देने की कृपा की जाय ।

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल के प्रदूषित उत्सर्जित जल को बागमती नदी में गिराने से जल का रंग काला और प्रदूषित हो रहा है, जिससे जीव-जन्तुओं मर रहे हैं । आम लोगों में महामारी फैल रही है, जिस पर शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाय ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, राज्य के 3.28 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर,2015 एवं जनवरी,2016 का, अब तो फरवरी भी हो गया का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, पूरे राज्य में शिक्षकों के बीच भारी आक्रोश है, मैं सरकार से इनके जल्द वेतन भुगतान की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, 5 महीना हो गया और पूरे बिहार के जो नियाजित शिक्षक हैं, हाहाकार कर रहे हैं, 5 महीना से उनको वेतन नहीं मिला है पूरे राज्य में । अध्यक्ष महोदय, सरकार बैठी हुई है, इसपर सरकार को जवाब देना चाहिए कि कब तक ये शिक्षकों को वेतन देंगे ? जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है । अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षक भूखा रहेगा तो कैसे स्कूल में जाकर शिक्षा देगा । सरकार बैठी हुई है, इसको संज्ञान में लेकर जवाब देना चाहिए कि कब तक जो है, शिक्षकों को वेतन मिलेगा अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय जी ने जो सवाल लाया है, वह बहुत भाईटल मुद्दा है । सारे शिक्षक सड़क पर हैं, सरकार बैठी हुई है, सरकार को बताना चाहिए कि 6 महीने से वेतन नहीं देने का क्या औचित्य है ? आप महोदय, आसन से निदेश दें माननीय मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : सरकार इसको देखेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर, सिधवलिया और बरौली प्रखण्ड के विद्युत उपभोक्ता गलत बिजली बिल से परेशान हैं । उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन देने के पश्चात् विभाग द्वारा सुधार नहीं किया गया है । हजारों की संख्या में बिजली बिल में गड़बड़ी को अविलम्ब सुधार कराने की सूचना देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल गोपालगंज जिले का नहीं है, पूरे बिहार का है और इसमें ऐसे-ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, एक-एक व्यक्ति के यहां दो-दो

बिल जा रहा है और जिस व्यक्ति ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, उसके यहां भी बिल जा रहा है । यह जो भारी गड़बड़ी है, यह जो प्राइवेट कम्पनियों को दिया गया है, वे लोग जाते हैं और नाम नोट कर लेते हैं और बिजली का बिल भेज देते हैं और इसको लेकर काफी परेशनी है अध्यक्ष महोदय । मेरा निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाय और सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया जाना चाहिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहरसा के डॉ0 आई0 डी0 सिंह से रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कोसी कमीश्नरी के चिकित्सकगण कई बार हड़ताल कर चुके हैं । सरकार आरोपी को अतिशीघ्र गिरफ्तार करावे ।

महोदय, पूरे कोसी कमीश्नरी के डॉक्टर भयाक्रांत हैं, पलायन की स्थिति है । लगता है कि शासन-प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है और पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है और हर डॉक्टर लगता है कि पलायन कर जायेंगे । महोदय, हम सरकार से चाहते हैं कि अविलम्ब अपराधी की गिरफ्तारी हो ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण सूचना । माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय,महोदय, किसानों के सवाल पर हमने आपसे आग्रह किया था, सरकार से जवाब के बारे में जानना चाहते हैं कि किसान के धान क्रय नहीं किये गये हैं, बकाये राशि का भुगतान महोदय नहीं हुआ है.....

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि तख्तियां न दिखाये ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, सरकार ने डीजल पर सबसिडी नहीं दिया है । किसान कौड़ी के मोल धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं । सरकार इसपर जवाब तो महोदय दे । हम सरकार से अपेक्षा करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार का इसपर जवाब होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

<u>सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,अशोक कुमार सिंह एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग/गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य) ।</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ''औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुराणों में आदि-गंगा के नाम से वर्णित पुनपुन नदी का अपने उद्गम स्थल नवीनगर शहर में स्थानीय लोगों के द्वारा

अतिक्रमण किया जा रहा है । इस नदी के बेड में ही नवीनगर के सोनपुरा से संघत तक अवैध निर्माण खड़े हो गये हैं । इस नदी में गंदे नाले का पानी, शौचालय का गंदा पानी गिरा दिया जा रहा है जिससे नदी का जल विषाक्त एवं पेयजल प्रदूषित हो गया है । उक्त नदी में छठ व्रतियों का पूजा स्नान भी होता है ।

अत: नगर पंचायत नवीनगर में पुनपुन नदी के बेड में अवैध भवन निर्माण को शीघ्र हटाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं । ''

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को सरकार का उत्तर सुनने का साहस नहीं है और एक ही सवाल को हर दिन उठाना चाहते हैं, कम से कम विपक्ष को सरकार का उत्तर सुनने का साहस भी होना चाहिए । सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, अभी शून्यकाल खत्म हुआ, अब ध्यानाकर्षण आने वाला है । सदन कार्य संचालन नियमावली से चलता है और ये लोग खड़े हो गये हैं .....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

और हंगामा से समस्या का हल नहीं होगा । माननीय विरोधी दल के नेता एकदम दो-दो मिनट में खड़े हो जा रहे हैं, लगता है कि सब प्रश्न का उत्तर एक ही मिनट में मिल जायेगा । इसलिए महोदय, मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको कार्य संचालन नियमावली का ध्यान रखना चाहिए, बाकी जो मेम्बर ध्यानाकर्षण देते हैं और अन्य प्रश्न को उठाते हैं, इनसे इनको कोई लेना-देना नहीं होता है, कार्य-संचालन नियमावली का भी ख्याल विपक्ष के नेता को करना चाहिए, यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय-कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय-कार्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा, इसके लिए दिनांक 1 एवं 2 मार्च, 2016 की तिथि निर्धारित है । वाद-विवाद और सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध है, विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्नप्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	79 मिनट
जनता दल, यूनाईटेड	-	70 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	52 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	27 मिनट
सी0पी0आई0,एम0एल0	-	03 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	04 मिनट

		कुल -240 मिनट

माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं वर्ष 2016-17 के आय-व्यय पर विमर्श कर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

(व्यवधान)

क्या हो गया आपको ? कुछ सुना दें क्या आपको, कुछ सुना दें, आपको कोई मतलब नहीं रह गया, एक शायर ने कहा महोदय । एक शायर ने कहा है हम इनको सुना ही देते हैं । मुफलिसी का यह आलम यह है दोस्तों कि आम बेचकर मंजर खरीद लाये हैं, यह किसके तालिम का असर है कि कलम बेचकर खंजर खरीद लाये हैं ।

(व्यवधान) आप बात तो सुनिए । अभी शुरू भी नहीं किया और आप शुरू हो गये । महोदय, आप क्यों ऐसे बैठे हैं, वित्त मंत्री जी आपका क्या हाल है, आप क्यों ऐसे बैठे हैं ? आप भी सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : आपने तो शुरू में ही उनको मुफलिस कह दिया ।

श्री नंद किशोर यादव : इनको नहीं, विजेन्द्र बाबू को कहा था । दिल को थामे हुए यूं बेकरार बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई दाव हार बैठे हैं । (व्यवधान)

महोदय, हम जानते हैं कि ये लोग मेरा समय किल करने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष : आप उसमें न फंसें ।

श्री नंद किशोर यादव : आपको भी ध्यान रखना होगा कि जितना समय ये किल करें, उतना हमको समय दे दीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : यहाँ से जब आप वहाँ गये हैं तो जान ही रहे हैं एक-दूसरे का ।

श्री नंद किशोर यादव : आपको क्या कहें ! वे रहते तो उनको कहते । हम तो उनके अदा पर फिदा रहने वाले लोगों में से हैं । वे रहते तो कुछ कहते । उनकी अदा पर तो हम फिदा रहते हैं....

अध्यक्ष : देखिए नंद किशोर बाबू, अदा-फिदा-जुदा, यह सब लगा रहता है । आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री नंद किशोर यादव : जुदा क्यों हो गये महोदय ? अब इसपर सुन ही लीजिये । अगर मुख्यमंत्री जी होते तो हम कहते, हम तो उनके पुराने चाहने वाले हैं । हम तो दीवाने हैं सदियों पुराने, चाहे तु माने या न माने । लेकिन क्या करें महोदय, हर पाँच साल, दस साल के बाद वे अपना साथी बदलते रहते हैं तो जुदा तो होंगे ही ।

अध्यक्ष : हमको तो यह लगा कि आपने जिन पंक्तियों को उद्धृत किया, उसके मूल शब्द को क्यों आपने छोड़ दिया.....

श्री नंद किशोर यादव : हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने या न माने । जिसके हम आशिक हैं, हर पंद्रह साल पर साथी बदलते रहें तो क्या उपाय है, जुदा तो होना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष : भाषण जारी रहे ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं कह रहा था, थोड़ा सूना-सूना भी लग रहा है, उधर से कोई शेरो शायरी और कविता का दौर कहने वाले लोग इस बार सदन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । खैर महोदय, मैं बजट भाषण पढ़ रहा था, महोदय, आप जानते होंगे कि मैं भी लगातार 20-21 वर्षों से सदन का सदस्य रहा हूँ और मैंनें हर बार सरकार जब सदन में बजट पेश करती है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, उस बजट भाषण को पढ़ने का भी अवसर मिलता है और सुनने का भी अवसर मिलता है लेकिन मैं जब

वर्त्तमान वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पढ़ रहा था, बड़े गौर से पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक संदेह पैदा हो रहा है पूरा भाषण पढ़ने के बाद, मैं उन श।ब्दों को कोट करूँगा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने पुस्तिका में कहा है । महोदय, बजट किसका है, यह बजट जिस दल के सदस्य हैं वित्त मंत्री जी, उस घटक दल का बजट है या इस सरकार का बजट है, यह किसका बजट है, यह मुझे जानने में दुविधा हो रही है ? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ वित्त मंत्री जी कि मैंने कई बार बजट को देखा है, मैंने सदन में बजट देखा है, मैंने वित्त मंत्रियों जी के भाषण सुने हैं, लेकिन कभी-भी मैंने यह नही देखा कि किसी वित्त मंत्री ने यह कहा हो, जो आपने कहा है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ । आपने कहा है, आपके बजट भाषण की जो पुस्तिका है, उसके पेज-3 का जो अंतिम पारा है, आप खोलकर देखें । आपने लिखा है, जरूरी कार्यक्रमों के लिए राशि मुहैया कराना, कार्यक्रम बनाना, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना और यह देखना कि इसका लाभ अन्तिम सीढ़ी के आदमी को जरूर मिले, यह हमारे नेता, सभी घटक तथा सरकार की जिम्मेवारी होगी । महोदय, कौन हैं आपके नेता? आप इस सरकार के वित्त मंत्री हैं, आपका नेता होना चाहिए मुख्यमंत्री, आप किसी और को नेता मान रहे हैं महोदय । आपने घटक का जिक्र किया, घटक क्या होता है, यह बजट तो कैबिनेट पास करता है । याद करिए विजेन्द्र बाबू, जब पिछली बार मैंने इस प्रकार के सवाल खड़े किये थे तो आपने खड़ा होकर कहा था कि बजट कैबिनेट से पास होता है । महोदय, जब कैबिनेट का बजट है तो यह घटक की बात कहां से आती है ? महोदय, इसमें नेता की बात कहां से आती है ? महोदय, यह साफ होना चाहिए । मैं अपेक्षा करूँगा कि वित्त मंत्री जी आपसे कि आप जब अपने बजट भाषण का जबाब देंगे तो जरूर इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह बजट किसका है ? महोदय, और आपने क्या कहा, आपने एक और बात कही, बजट भाषण की पुस्तिका का पेज-8 देखिए, 13वीं पंक्ति में आपने क्या कहा- महागठबंधन के सभी घटक एकजूट होकर इस दस्तावेज के बातों को जमीन पर उतारेंगे, इसमें आपको कोई संदेह हो रहा है क्या ? क्या आपको लगता है कि आपने जो बजट पेश किया है, वह बजट आपके सभी घटक स्वीकार नहीं करेंगे और आपने अपने भाषण में, अपने बजट भाषण में अपने संदेह को श।ब्द देने की कोशिश की है । आपने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि आवाम के सब्र का पैमाना न टूटे, आपको कोई संदेह हो रहा है, आपको लगता है कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह क्रियान्वित नहीं होगा, आपका ऐसा लगता है । आपने यह भी कहा है कि, इसमें एक पंक्ति बदल दिया, एक शब्द बदल दिया, डॉ0 लोहिया का जिक्र करते हुए आपने कहा था कि जिन्दा कौमें वक्त का इन्तजार नहीं करती । डॉ0 लोहिया ने कहा था कि जिन्दा कौमें पांच साल तक इन्तजार

नहीं करती लेकिन इन सब बातों का मैंने जिक्र आपके सामने इसलिए किया कि यह सारे श।ब्द जो लिखित रूप में आपके बजट भाषण में अंकित है, ये सारे श।ब्द, सारी पंक्तियां, सारे वाक्य इस बात के परिचायक हैं कि आप जो बजट पेश कर रहे थे, आपको विश्वास नहीं था, आपको इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या इस बजट को सरकार पूरा करेगी ? आपको इस बात का भरोसा नहीं था कि आप बजट में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसको सरकार पूर्ण करेगी, आपको इस बात का भरोसा नहीं था या तो आपको भरोसा नहीं था या यह सरकार, एक सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है । यह सरकार तीन भागों में बंटकर काम कर रही है, तीन घटक अलग-अलग सरकार के रूप में ले जाना चाहती है, इसलिए आपने अपने घटक का जिक्र किया, आपने अपने नेता का जिक्र किया, आपने सरकार का जिक्र बाद में किया, यह आपकी भाषा से परिलक्षित होता है महोदय । महोदय, जब मैं देख रहा था बजट भाषण, मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे बजट भाषण देखे हैं । बजट भाषण की शुरूआत कहां से होती है, इस बार ऐसी शुरूआत नहीं हुई महोदय । इस बार बजट भाषण की शुरूआत एक अलग प्रकार के चीज से हो गयी महोदय । सात निश्चिय, अगर आप पूरा गौर से देखेंगे बजट भाषण की पुस्तिका, आप बजट भाषण की पुस्तिका को पढ़कर देखें, लगता है कि पूरे बजट भाषण में तैयार करते समय सात निश्चिय की बात किसी ने जबर्दस्ती घुसाने का काम किया है, ठेलने का काम किया है । बजट के बाकी हिस्सों में सात निश्चिय के विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा है, सात निश्चिय के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए धन, राशि की व्यवस्था की गयी होगी, मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा, बाद में इसकी चर्चा करूँगा लेकिन बजट भाषण की पुस्तिका में जिस प्रकार से प्रारंभ में सात निश्चिय के श।ब्दों को ठूंसने का काम किया गया है, वह इस बात का परिचायक है कि दूसरे घटक ने अपनी बात जबर्दस्ती इनसे मनवाने की कोशिश की है, इस पुस्तिका में डलवाने की कोशिश की है । यह जो घटक बात है, यह जो घटक बात का बिखरा हुआ स्वरूप सरकार का दिखायी पड़ रहा है इस सरकार से, हम इस सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार इस बजट में दी गयी राशि को खर्च कर पायेगी या उसके बारे में कोई विचार कर पायेगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री नंद किशोर यादव : सुन लीजिए भाई, फिर कुछ आपको सुनायें क्या ?
आप आये हैं तो बैठें या आराम करें,
सिलसिला बात का चलता है तो चल पड़ता है,

सूबे के फिक्र में खोया हुआ अभी चुप रहिए,
बात करने से ख्यालों में खलल पड़ता है ।
(क्रमशः)

टर्न-9-शंभु/01.02.16

श्री नन्दकिशोर यादव : क्रमशः.....महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है दोस्त, अभी तो मुझे 53 मिनट बोलना है। अभी तो आप क्या-क्या करोगे, आप जानो, लेकिन बात दूसरे की सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो आपने पुस्तिका में नहीं छापी है- जवाब देना पड़ेगा वित्त मंत्री जी को। मैंने उन सपनों का जिक्र किया है जो आपके पुस्तिका में छपी हुई है। मैं और जिक्र करना चाहता हूँ। आपने यहां बार-बार कहा है महागठबंधन की सरकार- आपकी पुस्तिका के शब्द हैं और महागठबंधन की सरकार में आपने क्या कहा है ? पिछले 10 वर्षों में बजट भाषण का जो पृष्ठ-4 है उसके तीसरी पारा की पहली पंक्ति पढ़िये। आपने लिखा है कि बिहार ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आपने लिखा है और मैं सोच रहा था और मुझे याद आ रहा था 2011, मुझे याद आ रहा था 2010- मैं उन पंक्तियों को उदृत करूंगा, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन है, ये महागठबंधन कहने का कौन अधिकार दिया। आप जब महागठबंधन की बात कर रहे थे। आपके महागठबंधन के अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे वे आपको छोड़कर चले गये तो आपको महागठबंधन कहने का अधिकार कैसे हो गया, हां गठबंधन कहने पर मुझे आपत्ति नहीं है, महागठबंधन कहने के अधिकार आपको नहीं है। अगर आप महागठबंधन की बात करते हो तो आपको 10 साल की बात नहीं करनी चाहिए, 10 साल की बात कहने का अधिकार नहीं रहा। आपको 60 साल की बात करनी चाहिए। 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया बिहार के अंदर- जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। 15 साल तक राजद ने शासन किया बिहार के अंदर जिस राजद के साथ आपका गठबंधन है। 10 साल एन0डी0ए0 की सरकार रही तो कुल 7 साल हो गये इसलिए आपको 7 साल का जिक्र करना चाहिए, 10 साल का जिक्र नहीं करना चाहिए। 55 साल का जिक्र करना चाहिए, लेकिन आपने 10 साल का जिक्र किया है। आपसे जानना चाहता हूँ इसका अर्थ यही है कि आपने 15 साल में कोई काम नहीं किया, 15 साल में बिहार के विकास के बारे में कुछ नहीं किया। आपने स्वीकार किया इस बात को और 30 साल में कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लिए कुछ नहीं

किया ये आपने स्वीकार किया है। आप ही ने कहा है 10 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। कौन देगा इन 45 सालों का हिसाब, 30 साल के कांग्रेस का हिसाब, 15 साल आर0जे0डी0 का हिसाब- वित्त मंत्री जी आपको भी देना पड़ेगा। जब आप महागठबंधन की सरकार की चर्चा कर रहे हैं। 50 साल तो कांग्रेस शासन केन्द्र में भी थी। किनका-किनका जिक्र करें आपके सामने, आपके कैसे-कैसे विचार बदल रहे हैं।

आप जिस 10 साल के अभूतपूर्व प्रगति की चर्चा कर रहे हैं वित्त मंत्री जी, जिस 10 साल की अभूतपूर्व प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। उसके बजट में आपने 2011 में क्या कहा था। मैं आपको कोट करना चाहता हूँ आपके बजट भाषण की फोटो कॉपी मेरे पास है। उससे मैं अक्षरशः आपके शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जो आपने कहा है मैं इसको कोट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको सुन लीजिए न, शायद आप भूल गये होंगे मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था, सारे भाषण मैं नहीं पढ़ सकता, केवल एक लाइन कोट करता हूँ। 24 हजार योजना के आकार में 13670 करोड़ सिर्फ केन्द्रीय अनुदान है और राज्य का जो अपना कर होगा वह 12500 के करीब का होगा। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि कृषि सहित राज्य के मौलिक अर्थव्यवस्था जो है, उसमें हो सकता है। भले आपको बुरा लगे मगर, प्राइमरी सेक्टर में इस सरकार ने एक तरह से यहां की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। महोदय, आपका भाषण है 2011 का, जब 2011 में तहस नहस कर रहे थे हम अर्थव्यवस्था को तब कैसे बजट भाषण में कह दिया कि 10 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह किसके कहने पर , किसके दबाव में कहा ? सच कब बोल रहे थे आप 2011 में सच बोल रहे थे कि 2016 में सच बोल रहे हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए आपके भाषण में, मैं इस बात की अपेक्षा करता हूँ। महोदय, सरकार के बजट भाषण को पढ़िये तो बजट भाषण में इस बात की विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी कि सरकार संसाधनों के बारे में क्या विचार करती है, कैसे क्रियान्वित करेगी, कैसे-कैसे पैसा आयेगा थोड़ा जिक्र है इसमें, लेकिन पूरे बजट भाषण को, वित्त मंत्री के बजट भाषण को पढ़ने का काम कीजिएगा आप तो आपको दिखायी पड़ेगा कि यह जो सरकार है, यह सरकार काम नहीं करना चाहती है। यह सरकार केवल राजनीति करना चाहती है और राजनीति के लिए एक चीज मिल गया है इनको। यह सरकार केवल केन्द्र सरकार के विरोध के नाम पर राजनीति करना चाहती है और पूरे बजट भाषण में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करने के बजाय जिन उपलब्धियों के बारे में ये फंसनेवाले हैं मैं उसका जिक्र करूँगा। ये केवल भारत सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके अपनी चमड़ी बचाने का काम कर रही है। क्या-क्या करना चाहते हैं आप, केवल भारत सरकार पर दोषारोपण करना चाहते हैं केवल अपनी कमी छुपाने के लिए।

क्या हाल है आपका ? अरे, याद कीजिए आप 2014-15 का वार्षिक कर संग्रह कितना था आपका केवल 22308 करोड़ रूपया का। आपने खुद भी स्वीकार किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े 7 हजार करोड़ रूपया कम हासिल होंगे आपको। आपने बजट बनाया है 1 लाख 44 हजार करोड़ रूपये का- इस 1 लाख 44 हजार करोड़ में आपके पौकेट का पैसा कितना है केवल- 29730 करोड़ रूपया। यह केवल आपके जेब का पैसा है, बाकी पैसा कहां से आयेगा, कौन देगा पैसा ? ये पैसा क्या भारत सरकार से विभिन्न योजना में नहीं मिलनेवाला है ? क्या आप रिण नही लेंगे, क्या आप कर्ज नहीं लेंगे ? तो 29730 और आप गाली बक रहे हैं। आप केवल उसकी आलोचना किये जा रहे हैं। एक तरफ सहायता के लिए जाते भी हैं और दूसरी ओर केवल आलोचना करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी तो हालत यह हो गयी है कि जो भारत सरकार पैसा देती है उस पैसे को खर्च करने की ताकत भी आपकी सरकार में नहीं रह गयी है। यह सारे आंकड़े इस बात का गवाह हैं। आप कह रहे हैं कि मदद नहीं मांगेगे। केन्द्र सरकार के बारे में क्या-क्या कह रहे हैं आप और पहले क्या कहते थे। आज केन्द्र सरकार के बारे में आप जो चर्चा करते हैं, पहले आप क्या करते थे, 28 फरवरी, 2011 के बजट भाषण का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। महोदय, आपके कहे हुए बात से ही है मेरे कहे हुए शब्द नहीं हैं। आपने क्या कहा था- अब इसी किताब में जो आपने लिखा है जैसे अक्सरहां कहते हैं कि केन्द्र भरपूर मदद नहीं कर रहा है, बिजली की कमी इसलिए दूर नहीं हो रही है, कोयला मुझको नहीं मिलता है वगैरह-वगैरह। जो आपका स्टाइल है। आपको शायद याद हो कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आये थे अपने राज्य में जो पता नहीं आपके बीच में थोड़ा सा खटास भी हुआ था। मगर उस गांधी मैदान में उसी नरेन्द्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि मेरे तरफ एक रेगिस्तान है और दूसरी तरफ पकिस्तान है। बिजली के लिए, कोयला के लिए हम सेंटर के पास रोते नहीं हैं। बिजली के लिए, कोयला के लिए हम सेंटर के पास दौड़ते नहीं हैं, हम अपना इंतजाम खुद करते हैं। आपका भाषण है, मेरा भाषण नहीं है। अक्षरश: मैंने कोट किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज जब वित्तमंत्री नहीं रहते हैं।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : समय के साथ चेहरा भी बदल जाता है और बोली भी बदल जाती है।

श्री नन्दकिशोर यादव : मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो भाषण है, यह भाषण आपको अपने भी पढ़ना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं।

अध्यक्ष : ये तो खुद पढ़े थे।

श्री नन्दकिशोर यादव : आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं और मैं जाननता हूँ कि आप अपने पुराने भाषणों को जरूर पढ़ते होंगे और पुराने भाषणों को पढ़ने के बाद आपका यह बजट भाषण

इसीलिए उन शब्दों का जिक्र किया मैंने आपके मन में कचोट है, आपके मन में कष्ट है, आपके मन में इस बात की निराशा है, आपके मन में आशंका है कि आप जो बजट पेश कर रहे हैं वह बजट ठीक है कि नहीं ठीक है, पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, ये संशय आपके मन के अंदर है। यह आपकी बात में जाहिर होता है, आपके बयान से भी जाहिर होता है। महोदय, खूब भाषण दे रहे थे- 14 वें वित्त आयोग की चर्चा, कितना-कितना बार हुआ, कितना बोलते हैं 14वें वित्त आयोग पर, 14वें वित्त आयोग में कोई राशि कम मिल रही है ? ये हमारा दोष है क्या ? ये नरेन्द्र मोदी का दोष है क्या ? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप जानते हैं, आप इन बातों को नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी राजनीति है यह ? 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ- यू0पी0ए0 के शासन काल में 2 फरवरी, 2013 को और वित्त आयोग ने रिपोर्ट कब दी 15 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रपति को वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी। वित्त आयोग कौन-कौन कारक तय करेगा, हम तय करते हैं क्या ? किन-किन कारकों के आधार पर वित्त आयोग राशि आवंटित करेगा यह केन्द्र सरकार तय करती है क्या ? प्रधानमंत्री तय करते हैं क्या , नरेन्द्र मोदी तय करते हैं क्या ? आप बार-बार हमारे उपर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। आप सबसे वाकिफ हैं, लेकिन सबसे वाकिफ होने के बावजूद भी जानबूझकर के आप बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे है। अरे, आपको धन्यवाद देना चाहिए नरेन्द्र मोदी को। पहले भी वित्त आयोग ने अनुशंसा किया है, पहले भी वित्त आयोग ने भी केन्द्रीय करों में जो राजस्व होता है उसकी हिस्सेदारी के बारे में राज्यों के हिस्से के बारे में पहले भी कितनी बार अनुशंसाएं हुई हैं। कितना माना भारत सरकार ने ? आप उद्घाटित करने का काम कीजिए। कितने माना अनुशंसाएं किनकी मानी जाती रही, लेकिन धन्यवाद दीजिए नरेन्द्र मोदी जी को कि अगर वित्त आयोग ने कहा कि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 परसेंट किया जायेगा तो अक्षरशः उसका पालन करने का काम नरेन्द्र मोदी ने किया है। राज्यों की राशि को बढ़ाने के लिए आप उनको धन्यवाद दीजिए और आप उल्टा हमपर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। कैसी राजनीति करने का काम कर हैं। हम गलत कह रहे हैं तो बताइये आप। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कोई छुपकर तो नहीं कह रहा हूँ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : नन्दकिशोर जी, बहुत धैर्य से आज हम आपको पूरा सुनना चाहते हैं और फिर कल उत्तर में आप भी धैर्य से सुनियेगा, भागियेगा मत।

श्री नन्द किशोर यादव : मेरी तो चिन्ता क्या है , मैं चिन्ता आपको सुना देता हूँ - क्या गजब के दोस्त हैं , तुम सैयाद हो लूट कर गुलशन हमारे साथ खूब की सूबे पर इनायत,खूब की सूबे की इनायत , आपने पर कतर कर कह दिया आजाद हो` ,आप क्या जवाब दीजियेगा ,मुझे मालूम है, मैं कहना चाहता हूँ 1

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : कविता पढ़ने का मौका तो मिल रहा है 1

अध्यक्ष : कहिये न यह तो आप पहले भी पढ़ते थे 1

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, वित्त मंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूँ वित्त मंत्री के बगल में जो आदमी बैठे हुए हैं उनका भी सम्मान करता हू लेकिन जरा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी 1

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, दुख है कि एक से दो नंबर पर चले गए कविता नहीं पढेंगे तो काहे के लिए चिन्ता इनका वित्त मंत्री जी की कर रहे है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय , जो लोग यह बात कह रहे हैं उनको अपनी जमीन का भी एहसास होना चाहिए महोदय, जहाँ मुख्यमंत्री के बगल में बैठा करते थे मुख्यमंत्री के बाद तीन मंत्री बैठते हैं उसके बाद बैठने का काम कर रहे है इनको इस बात का सिला होना चाहिए कि क्या हो रहा है 1

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का नियम है कि बच्चे जब बड़ा होते हैं तो गार्जियन जगह अलग कर लेते हैं इनको क्या हो गया कि प्रेम बाबू के बगल में आ गए 9 बढ़िया है !

श्री नन्द किशोर यादव : प्रकृति के नियम की बात कर रहे हैं लेकिन प्रकृति के नियम में इनको शायद यह नहीं सिखाया गया होगा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए 1 प्रेम कुमार हमारे बड़े भाई हैं हमने सम्मान करके इनको बैठाया है आपको इस बात का कष्ट क्यों हो रहा है 9

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस अन्ताक्षरी को समाप्त करिये और अपनी बात कहिये 1

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं आपसे कह रहा था 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जब 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा हुई 5 वर्ष में कितना पैसा मिला आपको 9 आपको 5 वर्षों में जो पैसा मिला 1 लाख 65 हजारा करोड़ रुपया और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर कितना पैसा मिला 9 4 लाख 9 हजार करोड़ रुपया, जहाँ 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपया मिला आपको 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 4 लाख 9 हजार करोड़ रुपया मिलेगा और आप कह रहे हैं कम है 1 कौन हिसाब करने का काम करते हैं 9 क्या गुणा भाग कर रहे हैं यह परसेंटेज वह परसेंटेज कैसी बात कर रहे हैं ,आपको मालूम होना चाहिए वित्त मंत्री जी 1 उत्तर प्रदेश में

सबसे ज्यादा पैसा मिला चूंकि आबादी ज्यादा है , उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राशि बिहार को मिली है 1 दूसरे राज्य को नहीं मिली है 1 और जो बिहार को राशि मिली है कर्णाटक, आन्ध्र प्रदेश। और तमिलनाडु से दुगुनी राशि मिली है आपको मिली है अरे जो गुजरात हमारा थौ जिसके मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री हैं उस गुजरात से तिगुणी राशि हमारे बिहार को मिली है 1 बंगाल और महाराष्ट्र से 1 लाख। करोड़ रुपया ज्यादा बिहार को मिला है यह तो हमारी सदाश्यता थी कि हमने आपके हिस्से को काटने काम नहीं किया चूँकि राज्य हमारा था,यह राज्य देश का हिस्सा है ,यह राज्य कोई पार्टी का हिस्सा नहीं था लेकिन आप गलतबयानी का काम रहे हैं 1

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय,मजाक की बात नहीं अभी अभी नन्द किशोर बाबू ने उस रेफरेंस को पढ़ा उस नोटिफिकेशन को पढ़ा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ वित्त आयोग ने रिपोर्ट कब दिया और अभी अभी कह रहे हैं कि हमने दिया और हमारा राज्य गुजरात ,आप बिहार के हैं भाई वित्त आयोग की अनुशंसा में आपकी क्या भूमिका है ? आप ही ने खुद कहा है 1

श्री नन्द किशोर यादव : आप टाईम किल मत करिये ,महोदय,केवल मैं यह कहना चाहता हूँ कि गलत बयानी बंद करिये 1 अगर 14 वें वित्त आयोग की जो राशि मिली है उस राशि का उपयोग कैसे करियेगा इसका विचार करिये और गलत बयानी करने का काम मत करिये 1 दोषारोपण करने का ,गलत ढंग से बयानी करने की कोशिश मत करिये 1 यह मैं कहना चाहता हूँ 1 आपको मालूम नहीं है कि इस बार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण। आपको ज्यादा पैसा मिलना है शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए आपने कभी स्वीकार किया, इसके लिए आपने धन्यवाद दिया 1 आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाआ और शहरी निकायों के लिए पहले की तुलना मं चार गुणा ज्यादा पैसा मिलेगा महोदय , 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर इन पंचायत राज संस्थाओं को और शहरी निकायों को 5 वर्ष में केवल 5 हजार 682 करोड़ रुपया मिले थे और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अगले पांच साल में बिहार को मिलेंगे 23694 करोड़ रुपया , आपको कम लगता है आप कैसे खर्च करेंगें , इसका उपाय नहीं करना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं केवल आलोचना करना चाहते हैं , क्या कर रहे हैं आप ? जो आपको पैसे मिल रहे हैं केन्द्र प्रयोजित योजना के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ 1 मेरे पास समय की भी सीमा है लेकिन क्या हाल है आपका ? आप कहेंगे कि हम तो नहीं थे 1 यह कहने से काम नहीं चलेगा ? 10 साल की खूब प्रशंसा की है आपने , क्या हुआ 12- 13 में? केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो पैसा आया था 5 हजार 23 करोड़ रुपया लौट गया महोदय , 13-14 में 5785 करोड़ रुपया लौट गया , कौन जिम्मेवार है इसके लिए ? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा ? आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलता पैसा नहीं मिलता और जो पैसा

आपको मिलते हैं उस पैसे का उपयोग करने की ताकत आपमें नहीं है 1 उस पैसे को खर्च करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है आप दोषारोपण करना चाहते हैं 1 आप कहते हैं विशेष सहायता 1 विशेष। सहायता से हमने कब इन्कार किया है 9 हम अभी पैकेज के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं 1 बहुत समय लगेगा समय मिलेगा तो कहूँगा आपसे 1 लेकिन आपको मालूम है हमरा कमीटमेंट है और हम काम कर रहे हैं उसके अंदर , सब पर काम कर रहे हैं1 लेकिन आपको तो बीमारी है विरोध की राजनीति करने का ,आपको तो बीमारी है केवल इसके बारे में टीका टिप्पणी करने का ,आपने केवल काम करने की वजाय भारत सरकार पर टीका टिप्पणी करके कवेल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं 1 मेरे पास आंकड़े हैं, समय मिलेगा तो मैं उनको पढ़कर सुना दूंगा 1 आप बड़ा भाषण देते हैं बड़ा बजट बना दिया 1 लाख 44 हजार करोड़ का, अरे क्या बना दिया भाई 1 अरे भाई आपको भी याद होगा 1और बगल में जो बैठे हैं उनको भी याद होगा क्योंकि वे भी वित्त मंत्री हुआ करते थे मालूम है उनको ,पहले क्या होता था , पहले होता था जो भारत सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी थी जो योजनाएं भारत सरकार चलाती थी उसका पैसा आपके बजट में परिलक्षित नहीं होता था ,सीधे क्रियान्वयन एजेन्सी को भेजी जाती थी , वह आपके राज्य के बजट में नहीं दिखता था , आपके बजट का आकार थोड़ा छोटा दिखायी देता था लेकिन 2014-15 पिछले वित्तीय वर्ष से जब भारत सरकार ने तय किया कि जो उसके अनेक योजनाओं का पैसा है जो क्रियान्वयन एजेन्सी को सीधे जाता था वह पैसा राज्य के बजट में परिलक्षित होगा और जबसे वह परिलक्षित होने लगा आपके राज्य के बजट का आकार बढ़ा हुआ दिखायी पड़ता है और आप अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं बड़ा बजट बना दिया ,खूब राशि। ला दिया अरे कहाँ से राशि ला दिया , अरे भाई सच बोलने का साहस क्यों नहीं रखते हैं , सच बोलियेगा तो आपको फायदा होगा मैं फिर आपको एक बात कहता हूँ कि आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए 1 लेकिन एक विद्वान ने कहा है सिद्दीकी साहब सच स्वीकार करियेगा तो आपको फायदा होगा 1 एक विद्वान ने कहा है कि भूल होना प्रकृति है ,प्रकृति का नियम है भूल हो सकता है 1 मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना यह प्रगति है 1 इसको अगर स्वीकार कर लीजियेगा ,आगे बढ़ने का काम करियेगा , नहीं तो वहीं के वहीं रह जाईयेगा कोई उपाय नहीं बचेगा 1 आप कह रहे हैं इस नियम के परिवर्तन के बाद खूब पीठ थपथपा रहे है कि खूब काम किया खूब काम किया 1 महोदय, आजकल जोर चला हुआ है पूरे बजट भाषण में आप देखियेगा कि खूब ढोल पीटा गया है 7 निश्चय का , 7 निश्चच का ढोल पीट रहे हैं ! लगता है कि बड़ा तोप लेकर आ गए हैं 1 कोई नयी चीज खोज करके ले आए हैं 1 अरे भाई क्या है 7 निश्चय 1 पढ़िये तो जरा गौर से 1 आप तो शायद नहीं पढ़ें होंगे लेकिन आप आलोचना के लिए तो पढ़े ही होंगे सिद्दीकी साहेब के तग 2010 में हमारी सरकार बनी थी तो हमलोग हर साल 2005 में सरकार बनी थी ,2010 में सरकार बनी तो हर बार हमलोगों ने सुशासन के

कार्यक्रम घोषित किए थे ,सुशासन के कार्यक्रम 2005 से 2010 तक और सुशासन के कार्यक्रम 2010 से 2015 तक ें हमलोगों ने घोषित किया था और शायद इसबार भी आपलोगों ने घोषित किया होगा लेकिन सुशासन से कोई चिढ़ हो रही होगी इसलिए 7 निश्चय करना चाहते है, 7 निश्चय का ढोल बजाना चाहते हैं 1 क्या है भाई 9़ 7 निश्चय में एकाध बातों को अगर छोड़ दिया जाय तो वित्त मंत्री जी गौर से पढ़ियेगा तो सुशासन के कार्यक्रम 2010ें -2015 सं सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपने 7 निश्चय के बारे में लोगों के सामने पेश करने का काम किया है , कौन सी नयी बात है मैं आपको उदाहरण दूंगा और मैं कहना चाहता हूँ आरोप लगाना चाहता हूँ चूँकि सुशासन के कार्यक्रम 2010, 2015 के विभिन्न पहलुओं को आप ल्यागू नहीं कर पाए 1 आप विफल हो गए , फेल हो गए इसलिए आप जनता की आंखों में धूल झोकने के लिए 7 निश्चय का एक नया पिटारा खोलने का काम किया है 1 नयी चीज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं , यह सिखाने का काम आपने किया है 1 कोई अंतर नहीं है मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 1 आपने कहा घर घर बिजली , क्या बिजली मंत्री जी ,आपको छोड़ देना ठीक नहीं लगता है 1 आप बार बार यहॉ भाषण देते थे 1 हम जब कहते थे 2015 में बिजली नहीं पहुंचायें तो वोट मांगने नहीं आयेंगे तो मुख्यमंत्री जी भी खड़े हो गए फिर आप भी खड़े हो गए कि 15 नहीं कहा है, 15 नहीं कहा है 2016 तक करने वाले हैं कहा था न 9़ नहीं कहा था 9़ क्या हुआ यह 2016 का फरवरी बीत रहा ह,बीत गया है और आज मार्च का पहला दिन प्रारम्भ है ,10 महीना बाकी है 10 महीनों में क्या आप उस काम को पूरा कर पायेंगे 9़ मैं आपके भाषण को कोट करना चाहता हूँ1 आपने अभिभाषण दिया है 1 याद करिये आप 2015-16 का बजट भाषण। पढ़कर सुनाना चाहता हूँ -

पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण। विद्युतीकरण। योजना के 12 वें प्लान के अंतर्गत 2927 अदद अविद्युतीकृत गांवों में से 10 हजार गांवों का विद्युतीकरण। किया जा चुका है शेष 2910 अदद गांवों का दिसम्बर 2016 तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा तथा शेष 2384 आंशिक विद्युतीकृत गांवों का दिसम्बर 2016 तक विद्युतीकरण। करने का लक्ष्य निर्धारित है 1

क्रमश :

श्री नन्द किशोर यादवः क्रमशः आपने कहा था, (व्यवधान) अभी तो शुरू किया है, आपने क्या कहा, आपने 2016 तक ...

अध्यक्ष : नन्द किशोर बाबू, आपका आधा से अधिक समय बीत गया है, आप कह रहे हैं शुरू किया है ।

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, मैं क्या करूँ? महोदय, अगर वित्त मंत्री को डेढ़ घंटा बोलने की अनुमति दे सकते हैं तो मेरे साथ अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। मुझे भी उतना समय देना चाहिए । मुझे तो ज्यादा समय देना चाहिए महोदय, चूंकि मुझे जिस दृष्टि से देखना है वह दृष्टि तो इनकी हो ही नहीं सकती है । वस्तुतः दबाव की राजनीति कर रहे हैं महोदय । वह तो दबाव में बेचारे बनाने का काम कर रहे हैं । दबाव में पढ़ने का काम कर रहे हैं । मुझे स्वतंत्र होकर बोलने का अधिकार है महोदय । इसलिए थोड़ा रियायत करने का काम करिए । मुझे यही आपसे अपेक्षा है ।

क्या हो रहा है महोदय ? अब आप कह रहे हैं, आपने इस बजट भाषण में क्या किया ? आपने इस बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 2018-19 तक इस काम को पूरा करेंगे । अगले दो साल में पूरा करेंगे । क्या हुआ? आप रोज बात बदल रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्र0 यादवः महोदय, माननीय नन्द किशोर बाबू जी को दर्द हो रहा है । आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी को आपने डेढ़ घंटा दिया, एक घंटा 40मिनट दिए और मुझको एक्को घंटा बोलने नहीं दे रहे हैं । अब महोदय, इनकी सदस्य संख्या हो गई अब 53, यहां वित्त मंत्री जी की सदस्य संख्या है ...(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, आपने 2000, दो साल का काहे रख दिया, चूंकि भारत सरकार ने कहा 2018 तक हम संपूर्ण देश में विद्युतिकरण का काम पूरा करेंगे तो भारत सरकार के पैसे से विद्युतिकरण का काम पूरा करने के लिए आपने लक्ष्य 2016 को बढ़ा कर 2018 करने का काम किया । किसके ऑख में धूल झोंकना चाहते हैं ? किसकी ऑख में धूल झोंकना चाहते हैं ? क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार के पैसे से घर-घर बिजली पहुँचाने का काम हम करेंगे ? क्यों नहीं स्वीकार करने का काम करते हैं ?

महोदय, क्या कहा आपने ? आपने कहा, घर-घर पक्की गली-नाली। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में । सुनने में बड़ा अच्छा लगता है घर-घर पक्की

गली-नाली । कैसी बात कह रहे हैं आप ? कोई पहली बार कह रहे हैं आप ? महोदय, आपने लिखा है किताब में, शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा । आपने लिखा है शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा । सभी गांव-शहरों में गली-नाली का निर्माण किया जाएगा । बड़ा अच्छा लगता है । लगता है बड़ा चमत्कार होने वाला है । मैं आपको कहना चाहता हूं सुशासन के जो कार्यक्रम थे, बिजेन्द्र बाबू, आपने जरूर पढ़ा होगा । सुशासन के कार्यक्रम 2010-15 की पुस्तिका । हमारे पास उसकी कॉपी है । उसके पृष्ठ-15 पर जो ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है , उसमें आपने क्या लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं । उसमें लिखा है- आपने 2015 तक सभी टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने तथा टोलों की गलियों का पक्कीकरण और नाला निर्माण का कार्य किया जाएगा । यह 2010-15 की पुस्तिका में आपने छापने का काम किया है । क्या हुआ उसका ? पांच साल बीत गए । आपने पहले वादा किया था बिहार की जनता से 2010-15 के कार्यक्रम में घोषणा किया आपने, 2015 तक सभी गली-नाली को पक्कीकरण करने काम करिएगा, सभी टोलों को जोड़ने का काम करिएगा, फिर वही बात दुहरा रहे हैं । कह रहे हैं नया बात लेकर आ रहे हैं, यह क्या कह रहे हैं आप ? क्या किया आपने, कौन सा काम शुरू किया, क्या हो गया आपके विभाग को, ग्रामीण कार्य विभाग यह काम देखता है महोदय । संपर्क पथों को बनाने का काम ग्रामीण कार्य विभाग देखता है । क्या हाल है ग्रामीण कार्य विभाग का ? 2013-14 में योजना प्रारम्भ हुई । 37,908 कि0मी0 सड़क बनाने का निर्णय लिया आपने और उस समय इस सदन के अंदर घोषणा किया गया ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री के द्वारा, अगले पांच साल के अंदर ढ़ाई सौ से उपर के सारे बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। क्या हुआ, 2013-14 के बाद, तीन साल तो बीत गया, 2013-14, 2014-15, 2015-16, तीन साल बीत गए, कितने किलोमीटर सड़क बने ? 37,908 कि0मी0 में कितने सड़कें बनी ? बड़ी मजेदार बात है महोदय । 2013-14 में भाषण दिया कि पांच साल में बनाएंगे, 2014-15 में भाषण देने आए तो महोदय, तब भी कहा कि पांच साल में बनाएंगे और 2015-16 में भाषण देने आए, तब भी कहा कि पांच साल में बनाएंगे, महोदय । महोदय, 2010-15 के कार्यक्रम में 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा पांच साल में, गली-नाली पक्की करेंगे, 2013 में कहा, गली-नाली पक्की करेंगे पांच साल में, 2010 में भी कहा पांच साल, 2013 में भी कहा पांच साल, 2014 में भी कहा पांच साल, 2015 में पांच साल और महोदय, अब 2016-17 में भी पांच साल का राग अलापने का काम कर रहे हैं । कौन-सा गणित आपका है, कौन-सा पहाड़ा पढ़ने का काम कर रहे हैं ? किस स्कूल में पढ़ने का काम किया है ? पांच साल कभी सड़कों

के मामले में खतम होगा कि नहीं होगा, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा वित्त मंत्री जी । पांच हजार किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई अभी । क्या-क्या किया आपने ? मुख्यमंत्री नगर विकास योजना आपने समाप्त कर दिया । मैं आऊंगा विधायकों के मामले में कौन-कौन सा दंड आपने दिया है, उसकी चर्चा आगे करूंगा । आपने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना समाप्त कर दिया और कितना पैसा दिया आपने ? यह सड़क बनाने का काम कौन करता है ? मुख्य रूप से ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में कितनी राशि आपने दी है ? कितनी बढ़ोत्तरी की है ? है ध्यान आपको ? है आपको इसकी जानकारी ? जानकारी भी नहीं आपको लगती है महोदय ? आप कैसे बनाएंगे ? कैसे पूरा करेंगे ? आपको इस बात का खुलासा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यह काम कैसे होगा ? आपने एक और नारा दिया , एक और आपका निश्चय है - निश्चय है हर घर नल का जल । बड़ा अच्छा है । महोदय, सुशासन का कार्यक्रम पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं । सुशासन के कार्यक्रम में भी 2010-15 में आपने कहा था । महोदय, कोई बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं महोदय । मेरे पास पुस्तिका है, पुस्तिका के पृष्ठ का जिक्र करता हूं मैं और जो बातें हैं सुना रहा हूं मैं । आपने 2010-15 में क्या कहा था सुशासन के कार्यक्रम में, आपने कहा था- राज्य के सभी शहरों और गॉवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड पर कार्रवाई की जाएगी । उसमें दूसरी पंक्ति आपकी है- फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्त्ति की जाएगी, और तीसरा आपने कहा था-बिहार से बहने वाली नदी सतही जलश्रोतों से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यह जो 2010-15 के कार्यक्रम के पांच साल बीत गए, नई सरकार बन गई, इस पांच साल में इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेवारी आपके सरकार की थी, तो क्या होगा इन कार्यक्रमों का ? क्या हाल है इन कार्यक्रमों का ? स्वच्छ जल की बात तो छोड़ दीजिए, गंदा पानी भी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, यह हालत है बिहार के नागरिकों का और दूषित जल के कारण बीमारियां हो रही हैं । पटना जिले के अंदर लोग मर रहे हैं बीमारियों के कारण । जब राजधानी के लोगों को पीने का पानी आप नहीं दे पाते हैं तो कौन-सा काम करिएगा ? क्या निर्णय थे आपके, कैसे निर्णय बदल गए आपके ? आपके निर्णय थे, आपने कहा है सतही जलश्रोतों से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । चूंकि आपकी सरकार है, आपको मालूम है कि भूगर्भ जल की कमी हो रही है । भूगर्भ जल नीचे जा रहा है । अगला वर्ल्डवार पानी के सवाल पर होगा । उस समय सरकार की मंशा, बिहार के मुख्यमंत्री की मंशा थी कि सतही जल का उपयोग करेंगे, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे । लेकिन क्या किया आपने ? कैसे-कैसे संगत में

कौन-सा निर्णय हो गया ? आपको याद है इस सतही जल के उपयोग के लिए पटना के अंदर पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए निर्णय हुआ था । नुरूम ने एक योजना बनाई थी लगभग साढ़े चार सौ करोड़ की योजना, जिस नुरूम की योजना के तहत गंगा के पानी को शुद्ध करके पूरे पटना शहर में 72 टैंक बना करके लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय आपकी सरकार ने लिया था और सरकार ने टेंडर किया था । काम प्रारभ्भ हो गया । 18जगह टंकी का निर्माण का काम भी आधा-अधूरा हो गया। ठीकेदार भाग गया । काम पूरा नहीं हुआ और आज आपकी सरकार का निर्णय हो गया कि हम सतही जल श्रोतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे । कौन परिवर्त्तन हो गया ? क्यों बदलाव आ गया ? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, जब पांच साल पहले आपकी नीति थी, आपके सरकार की नीति थी कि सतही जल श्रोतों के इस्तेमाल करने का काम हम करेंगे, भूगर्भ जलों का इस्तेमाल हम कम-से-कम करें, फिर आप भूगर्भ जल का इस्तेमाल करने का ही निर्णय क्यों किया आपने ? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा ।

महोदय, आपने क्या हाल कर दिया ? चापकल योजना बंद कर दिया । आप कह रहे हैं, हर घर में हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे, पहुँचाइए आप पानी, और आप पहुँचाइवे करिएगा चूंकि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने नगर निकायों के लिए और स्थानीय पंचायतों के लिए धनराशि में बढ़ोत्तरी कर दी है । हर पंचायत को 80लाख से एक करोड़ रूपया मिलेगा । आपको मालूम है कि हर नगर निकाय को करोड़ों रूपया मिलेगा । आपको उस पैसे का इस्तेमाल पानी के लिए, नल के लिए और रोड के लिए करना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन एक बार कह तो दीजिए न कि हम भारत सरकार के पैसे से लोगों तक पानी पहुँचाने का काम करने वाले हैं । हम भारत सरकार के पैसों से लागों के घरों, गली और नाली का काम करने वाले हैं । कह तो दीजिए एक बार । कहने में संकोच क्यों करना चाहते हैं ? महोदय, आपने चापाकल बंद कर दिया । मैं आगे विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, चापाकल बंद कर दिया आपने । पांच साल के बाद आपका क्या यह योजना पूरा होगा ? जिन गांवों के अंदर घर-घर पानी पहुँचाने का काम पांचवें साल होगा, चार साल वहां के लोग क्या पीएंगे महोदय ? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा ।

महोदय, गर्मी के कारण जो हाहाकार मचा है, पी.एच.इ.डी के बजट में कितनी बढ़ोत्तरी हो रही है आपकी ? बजट में आपको इस बात की चर्चा करनी चाहिए। महोदय, आपने कहा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान । महोदय, खुले में शौचमुक्त, समृद्ध और स्वच्छ बिहार के लिए. हर घर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी । महोदय,

फिर मैं आपको सुनाना चाहता हूं । सुशासन के कार्यक्रम 2010-15 की पुस्तिका के पृष्ठ-11 पर पेयजल स्वच्छ और शीर्षक के अंतर्गत आपने कहा है कि राज्य के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक अलग प्राधिकार का गठन किया जाएगा ... क्रमशः

टर्न-12/राजेश/1.3.16/

श्री नंदकिशोर यादव, क्रमशः- जो इसे अगामी पॉच वर्षों में पूरा करेंगे, क्या हुआ, पॉच साल बीत गये, सुशासन के कार्यक्रम के पॉच साल बीत गये, हर घर में शौचालय बनाने का क्या हुआ, क्यों नही बना, आप फिर से एक नया आडंबर खड़ा करके हर घर में शौचालय, जनता का सम्मान, नया निश्चय, सात निश्चय, क्या तमाशा खाड़ा करना चाहते हैं आप, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा । महोदय, मैं सुनाना चाहता हूँ 2015-16 का बजट भाषण उस समय की जो मंत्री थी, उन्होंने 9 अप्रील 2015 को भाषाण दिया था इसी सदन के अंदर में, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में स्वच्छता की स्थिति के लिए कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार दो करोड़ तेरह लाख सनतानवे हजार 335 परिवार, जिसमें से अब तक 9 अप्रील, 2015 तक 48 लाख 22 हजार 730 घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है, क्या होगा, पॉच साल में आपने वादा किया था हर घर में शौचालय बनाने का, क्या आप बना पाये, आप दो करोड़ 13 लाख में केवल 48 लाख बाकी का कौन जिम्मेवार हैं, आप जान गये हैं कि भारत सरकार स्वच्छता मिशन लागू कर रही है,आप जान गये है भारत सरकार घर-घर में शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त धन राशि। देने वाली है,तब आपने नया नारा गढ़ लिया कि स्वच्छता अभियान चलायेंगे,घर-घर में शौचालय बनायेंगे, सात निश्चय लागू करेंगे,भारत सरकार के द्वारा दिये गये पैसे से अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं,अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, आप लीजिये लेकिन एक बार नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कर दीजिये,तब हम मानेंगे कि आपको सच बोलने का साहस है ।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य नंदकिशोर जी आपके दल के लिए आवंटित समय 52 मिनट में 45 मिनट हो गया ।

श्री नंदकिशोर यादव:- अभी तो है न ।

अध्यक्ष:- हमको तो इस बात का एहसास है कि अभी आप घंटो बोल सकते हैं लेकिन समय तो अब सात ही मिनट बच रहा है ।

श्री नंदकिशोर यादव:- महोदय,आपने अपने बजट में इस बात की चर्चा की है,आजकल एक नया जुमला चल गया है मिशन मोड, मिशन मोड, लगता है कि मिशन मोड कोई नया बंदूक आ गया है, जो गोली सीधे मारता है तो क्या है मिशन मोड,आपने लिखा है कि इन निश्चयों को संकल्पों को मिशन मोड में क्रियान्वयन पर्यवेक्षण कार्य हेतु उपर्युक्त संस्थागत व्यवस्था की जायगी,यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है,आपने जिन बातों का उसमें चर्चा किया है क,ख,ग,घ,ड., पढ़िये गौर से वित्त मंत्री जी,यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, सुशासन के कार्यक्रम 2015 के अनुश्रवण में भी आपने वही व्यवस्था बनायी थी,आप कहेंगे तो मैं उसे पढ़कर सुना दूंगा लेकिन उसमें एक नया शब्द जरुर जोड़ा है मिशन मोड,यह मिशन कोई पहली बार नहीं है, क्या है मिशन मोड में,मैं आपको सुनाना चाहता हूँ,सुशासन के कार्यक्रम 2015 के पृष्ठ संख्या- 11 में आपकी सरकार ने लिखा था कि राज्य के सभी शहरों एवं गॉवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड पर कार्रवाई की जायगी,मिशन मोड को स्वच्छ जल पहुंचाने का निर्णय आपकी सरकार का था लेकिन यह मिशन मोड काम नहीं आया,हॉ एक परिवर्तन जरुर हो गया, मिशन मोड पहली सरकार ने तय किया, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया होगा, मंत्रिमंडल ने प्रयास किया होगा,सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रयास किया होगा लेकिन मिशन मोड के तहत सब जगह पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया लेकिन एक नया परिवर्तन जरुर हो गया है,इस बार शायद आपको लगता हो कि मिशन मोड जो नया सलाहकार आया है, उस नया सलाहकार के सलाह से मिशन मोड पूरा होगा तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । क्या करना चाहते हैं आप, किसको अधिकार देना चाहते हैं आप, किसके हस्तक्षेप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल को तोड़ करके अगर आप समझते हैं कि शासन कर लेंगे, सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित करने का काम करेंगे,तो आप भ्रम के शिकार हैं मंत्री जी, आप प्रशसन के मनोबल को तोड़ने का काम मत करिये,बाहरी हस्तक्षेप से शासन को मुक्त कराइये और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति के बाद ही आपका शासन आगे बढ़ सकत है, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं,हम सब के मन में इच्छा है बिहार आगे बढ़े,बिहार के कार्यक्रम लागू हो,आपके निर्णय जमीन पर उतरे, यह अलग बात है कि आपके अंदर क्षमता

नहीं है,यह अलग बात है कि आपके अंदर मंशा नहीं है,यह अलग बात है कि आप कर नहीं सकते हैं इसका लेकिन हमारी इच्छा जरुर है इसे जमीन पर उतारने का काम करें लेकिन हतोत्साहित प्रशासन से आप अपने काम को पूरा कर लेंगे, यह सपना देखाने का काम मत करिये महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आज मनोबल तोड़ने का काम शुरु हो गया है,सिनियर आई0ए0एस0 ऑफिसर स्वेच्छा से सेवानिवृति ले रहा है, यह सिलसिला कहॉ जाकरके रुकेगा, कहॉ खात्म होगा,मुझे मालूम नहीं है लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए । महोदय आपने सुशासन के कार्यक्रम 2010-15 के अनेक घोषणॉए हैं हवा में, आप कर्पूरी ठाकुर को अपना बताने का दावा करते हैं वित्त मंत्री जी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जरुर, आपने फिर इस बार कहा कि कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना सभी जिलों में समय के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा,क्या है यह, योजना 08-09 में प्रारंभ हुई और 38 जिलों में बनना था लेकिन मात्र 8 जिलों में बना है, 30 जिले बाकी हैं और क्या हाल है आपका,इन 30 जिलों के अंदर कब बनेगा मुझे मालूम नहीं लेकिन आपके मंत्री ने जब इसी सदन में पिछली बार भाषण दिया, तो उसने कहा कि 8 जिले में से 4 में काम प्रारंभ हो गया है, 4 में लोगों के रहने की व्यवस्था हो गयी है, मैं उनके भाषण को पढ़करके सुनाना चाहता हूँ, उस समय कहा उन्होंने कि 4 छात्रावास का उद्घाटन हो गया, फरवरी 2015 में 8 बने थे, फरवरी 2015 में 4 छात्रावास का उद्घाटन हो गया लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ लेकिन वही दूसरी ओर जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। आपके कैबिनेट ने तैयार किया, तो उस राज्यपाल के अभिभाषण में उन चार उद्घाटित छात्रावासों का कोई जिक्र नहीं हुआ, केवल कहे गये 8 बने, तो यह कब तक बने, तो इसतरह से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करने वाले आपसे मैं जवाब चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए बनने वाले छात्रावासों का निर्माण कभी होगा कि नही होगा, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इतने साल क्यों लगे, यह योजना 08 में ही प्रारंभ हुई, तो इतने साल क्यों लगे,आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा । महोदय, अनेक कार्यक्रम हैं, सुशासन के कार्यक्रम अनेक बिन्दु ऐसे हैं, महोदय पॉच साल में इस सरकार ने पूरा नहीं किया, मैं चूंकि इसको पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ महोदय इसलिए छोड़ रहा हूँ, यह क्या है, यह कैसा नियम है,यह बजट सत्र चल रहा है,जो सात निश्चय की बार-बार चर्चा करते हैं आप, उन सात निश्चयों में जो विभाग इनभौल्व है, जिन विभागों के माध्यम से आपको खर्चा करना है, जिन विभागों के माध्यम से आपको चर्चा

करना है,आपने उन विभागों पर चर्चा नहीं रखा, अनुदान मांगों पर उसपर चर्चा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्यों छोड़ दिया आपने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को, क्यों आपने छोड़ दिया स्वास्थ्य विभाग को, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, ग्रामीण कार्य विभाग को, पंचायती राज को, श्रम संसाधन को, क्यों आप इन विभागों पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग को तो समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ एक दौर चला है आपकी सरकार में, आपकी सरकार में बड़े भाईयों को दबाने का दौर चला है,ये छोटे भाई अपने बड़े भाई को दबाने का काम करते है, आपके बगल में बैठने वाले छोटा भाई अपने बड़े भाई को दबाने का काम करता है, शायद यह कारण होगा कि आपने स्वास्थ्य पर चर्चा करने का काम नहीं किया, आप क्या करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग जिन 7 निश्चय को आप लागू करेंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण विभाग को छोड़ दिया, आपने अपने स्तर को गिराने का काम किया, यह कौन सा काम करना चाहते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं, चूंकि मैं आपलोगों का पुराना मित्र रहा हूं, इसलिए आपकी कठिनाई को समझता हूं, आप जिन विभागों का लिस्ट बनाया है,आप सारे विभागों पर चर्चा करना चाहते हैं,उसमें आपने कोटा बॉटा है,आप घटक है,आप एक सरकार नहीं है,तीन घटक है, आर0जे0डी0, जद0यू0 और कॉग्रेस, तो आपने बॉट लिया कि पॉच विभाग के बजट पर आर0जे0डी0 भाषण देगा, पॉच पर जद0यू0 देगा और दो पर कॉग्रेस देगा, उस अनुपात में आपने चीजें बॉटने का काम किया, आपने बॅटवारा कर लिया, लेकिन जिनहित के मुद्दें पीछे छूट गये, जनहित के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, यह कौन सा नियम बनाना चाहते हैं आप, कौन सा बजट लाना चाहते हैं आप, किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं आप, घटकों के आधार पर निर्णय करने वाली सरकारें कभी भी जनता का कल्याण नहीं कर सकती है वित्त मंत्री जी, इस बात का घ्यान रखने का काम कीजिये ।

अघ्यक्ष।:- अब आपका दो ही मिनट बच रहा है, आप कहॉ उधर जा रहे हैं ।

श्री नंदकिशोर यादव:- दो ही मिनट है । वैसे मैटर है बहुत ।

अघ्यक्ष।:- आपको कमी कहॉ है ?

श्री नंदकिशोर यादव:- महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने क्या किया,आप जब-जब पावर में आते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री क्या विचार रखते हैं, विधायकों के अधिकारों के हनन का क्यों विचार उनके मन में आते हैं, क्यों विधायकों को अपमानित करने का काम करना चाहते हैं आप, आपने इस बजट भाषण के माघ्यम से क्या बताना चाहते है आप, आपने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को

बंद कर दिया, 101 नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र में हर पार्टी के लोग आते हैं, उनकी कोई योजना नही ली जायगी, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना बंद हो गया, नगर निकाय में विधायक अनुशंसा नहीं कर सकता है,आपने मुख्यमंत्री चापाकल बंद कर दिया, गॉव-गॉव में विधायक जाता है तो वहॉ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि चापाकल लगा दीजिये विधायक जी लेकिन अब विधायक को इस बात का अधिकार नहीं रह गया कि जहॉ वह चाहेगा वहॉ चापाकल लगा सकता है, तो आप कौन सा काम करना चाहते है ?

(क्रमशः)

टर्न-13/कृष्ण/01.03.2013

श्री नन्द किशोर यादव क्रमश : आपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को कट कर दिया, काट-छाट दिया। मैं सभी पार्टी के विधायकों से कहना चाहूंगा कि यह कोई बीजेपी का सवाल नहीं है, यह कोई एनडीए का सवाल नहीं है, हम जितने विधायक हैं सब को अपमानित करने का काम किया गया । इसलिये आज के बाद, इस बजट के पास होने के बाद कोई भी विधायक एक गली की अनुशंसा नहीं कर सकता । एक सड़क की अनुशंसा नहीं कर सकता । एक चापाकल की अनुशंसा नहीं कर सकता । क्या करेंगे हम ? झाल बजायेंगे क्या ? आप विधायकों के अधिकार में कटौती करना चाहते हैं । विधायकों को अपमानित करना चाहते हैं। इसे बार-बार आपकी सरकार ने करने का काम किया । 2010 में जो सरकार बनी, उस समय भी हमने विरोध करने का काम किया था । उस समय भी आपने इस तरह का काम किया और फिर 2015 में जो सरकार बनी है, फिर वही काम सरकार करना चाहती है । आपने कितने-कितने कटौती करने का काम किया ? आप क्या-क्या करना चाहते हैं ? क्यों विधायकों के अधिकारों का अंत करना चाहते हैं ? आप काम करके दिखा देते । आपने जो सोचा था, सारी योजनायें क्रियान्वित करके दिखा देते तो होती एक बात । आपको लगता है कि सलाहकार के आधार पर काम करेंगे । ठीक है तो हम पूरा काम कर लेंगे । मिशन मोड में काम करेंगे । विधायकों के अधिकार की कटौती करके ,विधायकों को जनता के बीच में अपमानित करके अगर आप चैन की बंशी बजायेंगे तो आपका सपना कभी पूरा होनेवाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखियेगा ।

महोदय, इस बजट में हवा-हवाई की बात कही गयी है । बिहार की जनता को बहार लाने का झांसा दिया ।

अध्यक्ष : अंतिम शेर पढ़ दीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय,झांसा दिया गया है। इस बजट में कई व्यवहारिक शून्य छोड़ दिये हैं । आपने ऐसा बजट पेश किया है, मानो पहले से आपने तय कर लिया हो कि घोषणाओं को लागू ही नहीं करना है । डपोरशंखी बजट, संसाधनों की कमी जल्दी आप को एक्सपोज करने का काम करेगी । यह बजट आम आदमी को धरासायी करनेवाला है। आप में तो क्षमता ही नहीं है। आप तो कर ही नहीं सकते । लेकिन आप मजबूर हैं । मैं जानता हूं कि चारो तरफ से दबाव के कारण आप न तो अपनी पार्टी की मन की बात कह रहे हैं, न अपने मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं, न बाकी सहयोगी घटक की बात कह रहे हैं और अंत में आपके मन से फूट जाता है, मेरे नेता, मेरा घटक और सरकार यह फूटने का इस बात का परिचायक है कि आपके अंदर आपकी जो हालत हो गयी है, मुझे कभी-कभी तरस आता है, मै आपका मित्र रहा हू । क्या आप चाहते हैं कि मैं चुप रह ?, क्या आप चाहते हैं कि विरोधी दल के लोग सरकार की कमियों के बारे में कुछ न कहें ? महोदय, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मैं चार पंक्ति कहना चाहता हूं -

तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीं नहीं है,
कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं ।
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,
मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हो सकता ।
मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं जरूर कहूंगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय सदस्य नन्द किशोर जी, दो लाईन का बड़ा मकबूल शेर है ।
इब्तदाये इश्क है, रोता है क्या,
आगे-आगे देखिये होता है क्या ।

श्री नन्द किशोर यादव : माननीय सिद्दिकी साहब, मैं आपका मित्र रहा हूं । आप जानते हैं । लेकिन मुझे आपकी भी चिन्ता है और आपकी चिन्ता में मैं दो पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा महोदय ।

अध्यक्ष : आप दोनों आदमी एक दूसरे के मित्र रहे हैं । लेकिन अभी आप दोनों को मिल कर आसन से मित्रता निभानी है । समय का ख्याल रखें ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं इनके लिए अंतिम दो पंक्ति कहना चाहता हूं । मेरे मन की चिन्ता क्या है, मै कहना चाहता हूं -

डूबनेवालों की फेहरिश्त में नाम न हो,
तेरे जैसा किसी तैराक का अंजाम न हो ।

महोदय, मुझे चिन्ता इस बात की है । मैंने इसलिए इस बजट की खामियों की चर्चा आपके सामने की है और सात निश्चय किस प्रकार से नये रूप में आपने ढालने का काम

किया है, केवल पुराने वादों को पूरा नहीं करने के कारण उसको एक नया स्वरूप देने का का किया है । मैंने इन बातों का जिक्र आपने सामने इसलिए की है कि हम सरकार के अंग हैं, जो आपकी सरकार है, वह सरकार अपने किये गये वादों को कभी पूरा नहीं करती है, यह सरकार केवल नारा लगाने का काम करती है । ,सरकार केवल वादा करने का काम करती है। लोगों को झांसा देने का काम करती है । लेकिन झांसा दे करके 5 सालों तक इंतजार नहीं हो सकता है। झांसा दे करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं हो सकता है । यह ध्यान आपको आ जाये । यह मैं आपको कहना चाहता हूं । आपने जिन 7 निश्चयों की चर्चा की है, उसको पूरा करने के लिये क्या आपके मन में संकल्प है, क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति है ? इसलिये मैं कहता हूं कि आपका यह संकल्प, आपका यह बजट पास भी हो जायेगा सदन के अंदर लेकिन आप पैसे को खर्च करने की ताकत नहीं रखते हैं । आप जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं । इसलिए मैं आपको एक पैसा देने के पक्ष में नहीं हूं और इतना कहता हुआ, आपकी सरकार को एक्सपोज करता हुआ, आपकी घटकवाद का विरोध करता हुआ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,डा0नवाज आलम । आपको 10 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

डा0 नवाज आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, भाषण के अगाज के पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और सत्ता पक्ष के तमाम साथियों के लिये एक शेर अर्ज कर रहा हूं

मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और बिहार की जनता की ओर से, आरा के जनपद की ओर से और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू यादव जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के माध्यम से तमाम देश वासियों को धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद इसलिए देता हूं कि हमलोग जैसे गरीब एक किसान के बीच पैदा होनेवाला आज सदन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, बजट में माननीय मंत्री ने बहुत ही विस्तार से तमाम चीजों को रखने का काम किया है । बजट में समाज के जो वंचित लोग थे, गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, जो बैक बेंचर थे, उन तमाम लोगों को इस बजट में समाहित करने का काम किया है । मैं अपनी ओर से इस सदन के माधयम से सरकार द्वारा पेश किये गये बजट का हम समर्थन करते हुये भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं । महोदय, प्रशंसा करते हैं इसलिए कि बजट भाषण में जो सात निश्चय कार्यक्रम को लाया गया है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री हरि नारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया ।)

यह एक अद्‌भुत कार्यक्रम हैं ! अद्‌भुत कार्यक्रम इसलिए है कि 'हर युवाओं को बल' के माध्यम से हर युवा बेरोजगार है, क्रेडिट कार्ड का जो उल्लेख किया गया है बजट में, सचमुच में यह सराहनीय कदम है युवा साथियों के लिये । इसलिये इस सदन के माध्यमा से हम बजट का पुरजोर समर्थन करते हैं । 'आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार' । महिला के अधिकार के मामले में बजट में जो 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया । इसके लिये हम बजट के माध्यम से इस सदन के माध्यम से भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं । हर घर में बिजली के मामले में माननीय सभापति महोदय जब हमलोग एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में गांव-गांव मे घूमते थे तो निश्चित रूप से हम करीब गांव के रहनेवाले हैं, 2-3 किलामीटर पर, सभापति महोदय, बिजली नदारत रहती थी, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का जो दृढ़ संकल्प है बिजली के मामले में घर-घर तक बिजली पहुचाने का, उसको सदा उन्होनें जमीनी सतह पर उतारने का काम किया है । इसलिये हम तमाम लोगों को अपनी ओर से इस सदन के माध्यम से हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं । साथ ही साथ,चौथा है 'हर घर में नल का पानी' । नल के पानी के मामले में सचमुच में अभी हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य बताने का काम कर रहे थे कि यह पुरानी योजना है । हम जानना चाहते हैं कि इस सामाजिक न्याय में बैठनेवाले लोग जो गरीब-गुरूवे है, इनके घरों में पानी घर-घर पहुंचाना, जो बैक बेंचर लोग हैं, उनके घरों में पानी पहुंचाना, क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता ? अगर इसको बजट में शामिल किया गया तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है । महोदय, शौचालय का निर्माण कराना, पक्की गली, नाली और साथ ही साथ 'अवसर बढ़े आगे बढ़ो' पढ़ने का जो नारा दिया, अवसर बढ़े आगे बढ़े। पारा मेडिकल कॉलेज खोलना, इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलना, पॉलिटेकनिक खोलना,नर्सिग होम खोलना, ए0एन0एम0 नर्सिग होम खोलना, हम तमाम साथियों को कहना चाहते हैं कि मंजिल पर पहुंचना है तो गलीचे पर नहीं, कांटे पर चलना सीखें, कांटे ही बढ़ा उेते हैं, रास्ता-ए-कदम के ।

क्रमश :

डॉ0 नवाज आलम(क्रमशः) साथियों जो 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है निश्चित रूप से हम मानते हैं कि यह एक टास्क है और उस टास्क को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उसे करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसलिए सभापति महोदय,आपके सामने वित्त विभाग द्वारा जो विभाग के मामले में योजना ली गयी, पथ निर्माण विभाग में कच्ची दरगाह-बिदुपुर की परियोजना। पटना शहर में मेट्रो का निर्माण यह तमाम योजनाएं सराहनीय कदम है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास के मामले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसमें जो बजट का प्रावधान किया गया है निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। लघु जल संसाधन विभाग उसमें बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, चीनी मिल उद्योग, नाबार्ड योजना तमाम चीजें जो हैं एक सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य विभाग में युवा मंत्री ने जो सराहनीय कदम उठाया है कि 3 नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, 12 पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैंसर संस्थान की स्थापना एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग के माध्यम से कांटी थर्मल पावर, बरौनी थर्मल पावर, नवीनगर फेज-1 एवं फेज-2 का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना, सरकार के द्वारा हर घर में बिजली लगातार पहुंचाना, एल0ई0डी0 लाईट लगाना एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति महोदय इसी तरह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। महोदय,अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से निश्चित रूप से कई लाभकारी योजनाएं ली गयी है जो सराहनीय कदम है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसमें कुछ संशोधन करते हुए जो राशि है जो अल्प राशि है उसको बढ़ाने की कृपा करें यह महोदय मैं मांग करता हूँ। श्रम संसाधन विभाग में श्रम संसाधन विभाग के मामले में माननीय बाल श्रमिक उन्नमूलन कार्यक्रम, बीड़ी मजदूर गृह निर्माण और मांझी श्रम योजना जो लागू किया गया है निश्चित रूप से वह एक सराहनीय कदम है। इसलिए सभापति महोदय,तमाम बिन्दुओं को हमलोगों के माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको लाने का काम किया है इसलिए हम जानना चाहते हैं तमाम जो है विरोधी दल के नेताओं से , अभी हमारे माननीय नन्द किशोर बाबू हमलोग के बजट के ऊपर बहुत सारे प्रकाश डालने का काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि वो भी इस धरती से आने वाले हैं। आरा की सरजमीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली लगाने का काम किया था। पूरे शाहाबाद के लोगों की ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने कहीं न कहीं धूमिल करने का बोली लगाकर बेचने का काम किया था उसका क्या हुआ? हम सदन के माध्यम से जानना चाहते है कि इस बजट में जो प्रावधान किया गया, किसी मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे युवा के रोजगार के

मामले में हो, 20-20 लाख का क्या हुआ? आपने आरा के रमना मैदान में घोषणा किया था हम पूछना चाहते हैं सभापति महोदय, उन्होंने कालाधन के मामले में भी कहा था, उन तमाम चीजों को एक छोटा-मोटा शेर कहता हूं विरोधी दलों के लिए-

वादे करते हो, भूल जाते हो,
खूब रस्मे वफा निभाते हो,
तेरे वादे पर जिये हम,
तो ये जान छूट जाना है,
कि खुशी से मर न जाते,
अगर एक बार होता तुम।

इसलिए साथियो हम बजट का पूरी तरह समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह:सभापति महोदय,बिहार के मतदाता के आशीर्वाद और प्यार से 10 साल का अनुभव मुझे भी मिला है और न्याय के साथ विकास हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर ले जाने में एक सार्थक और सकारात्मक भूमिका निभाने का मैंने भी प्रयास किया है और आज महागठबंधन की सरकार है और आदरणीय नीतीश कुमार नेता है। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बिहार की तस्वीर को बिहार के जनता के हित में, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सामाजिक समरसता समाज के अंतिम कड़ी में जो हमारे मतदाता खड़े हैं उनके लिए जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है उस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। पूरे देश दुनिया के लोग मानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास और उनके विकास रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने में आदरणीय मंत्री जी का जो बजट आया है, वह बड़ा ही स्वागत योग्य बजट है। मुझे 10 वर्षों के अन्दर में बड़ा अजीब सा आज महसूस हुआ सभापति महोदय। वे हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से यहां बिहार की तस्वीर को रखा, देश की तस्वीर को रखा और उन्होंने कहा कि 20-21 वर्षों का मुझे भी अनुभव है सामाजिक अनुभव है,राजनीतिक अनुभव है विधान-सभा में बैठकर समाज के अंतिम लोगों की सेवा करने का अनुभव है लेकिन उन्होंने हमारे ही तीर से अपने साथी की पोलिटिकल हत्या कर दी।महोदय, उन्होंने जो तस्वीर पेश किया, 2005 की तस्वीर उन्होंने पेश किया, 2010 की तस्वीर उन्होंने पेश किया और उन्होंने अपने जुवान से ही अपने आप को बिहार के जनता के सामने यह साबित करने का कार्य किया कि मैं काम में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कुर्सी में बैठने में विश्वास करता हूँ, सिर्फ नेतागिरी में विश्वास करता हूँ और बिहार की जनता

को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखलाने में विश्वास करता हूं। उन्होंने साबित किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के निश्चय पर, उन्होंने बड़ा ही अच्छा बहस किया लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका आज तक कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गयी और अभी तक उन्हें पता ही चल सका कि मैं कहां खड़ा हूँ और जिसका खामियाजा उन्होंने 2015 के अक्टूबर- नवम्बर के चुनाव में भोगा है। बड़ा ही ईमानदारी से उन्होंने भोगा है।(क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/01.03.16

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : ...क्रमशः... उन्होंने कहा कि 2005 का बजट, 2010 का बजट, भईया उस समय बजट किसने पास किया ? उस समय बजट किसने फ्लोर पर लाया ? अपने भाई का नाम लेकर भी उन्होंने उनको नीचा दिखाने का काम किया, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने बजट लाया कि हर घर में पानी पहुंचायेंगे, हर घर में शौचालय बनायेंगे, बिजली पहुंचायेंगे, क्या हुआ ? उस समय आप कहां थे ? उस समय आप बैठ कर वित्त मंत्री जी के पक्ष में पानी लेकर खड़ा थे, जिस तरह जेटली जी के पक्ष में नितीन गडकरी जी पानी लेकर खड़ा थे । वाह रे वाह ! हमलोग तो आते हैं कि बड़े भाई, बड़े गार्जियन हैं, संसदीय ज्ञान उनको हमसे अधिक मिला है, हमसे पहले आये, अच्छी बात बोलेंगे, स्वस्थ बात बोलेंगे, बिहार के विकास के लिए सकारात्मक पक्ष को रखने का कार्य करेंगे लेकिन वे अपने वित्त मंत्री पर आरोप लगाकर चले गए । चापाकल के सवाल पर, जल के सवाल पर पी0एच0ई0डी0 मंत्री पर वे आरोप लगाकर चले गये ।

आज आपके सामने चुनाव में महागठबंधन को जो जीत मिली और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो सात संकल्प लिया....(व्यवधान) भाई बिंद बाबू, क्षेत्र में ही रहते हैं, पटना में नहीं रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं और मैन टु मैन को जानता हूं, गली-गली को जानता हूँ, आँगन तक को जानता हूँ ।

हमारे वित्त मंत्री को आपको यह धन्यवाद देना चाहिये था, शायद हमको ऐसा महसूस होता है कि संसदीय इतिहास में वित्त मंत्री जी ने जिस इरादा के साथ, जिस नीति के साथ, जिस नियत के साथ बजट लाने का कार्य किया है, उस बजट को एक वर्ष में पूरा करने का इरादा बनाइये, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिये था । आज तो बजट आया ही है, इस बजट का तो खेल 01 अप्रील से शुरू होने वाला है । कम से कम एक वर्ष तो अपने धैर्य का परिचय दीजिये । एक बात तो है, अपने मन से

जानिये पराये मन का हाल । आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह हम हवा-हवाई की बात करते हैं, हो सकता है कि वही हश्र यहाँ भी न हो जाय । लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दुनिया के नक्शे पर बिहार को एक विकास, बिहार को एक मान-सम्मान और बिहार की जनता ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने का सार्थक प्रयास किया है ।

भाई बबलू जी बोल रहे थे, भईया कानून का राज है । उसी कानून के राज के तहत बबलू जी, मैं भी जेल की यात्रा पर गया, मैं इसको स्वीकार करता हूं । कानून सबके लिए एक समान है । झोपड़पट्टी के लिए कानून अलग, पैसे वालों के लिए कानून अलग, विधायकों के लिए कानून अलग, सांसदों के लिए कानून अलग ? यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत का लोकतंत्र है कि गरीब को न्याय नहीं मिले ? पैसे वाले पैसे के बल पर न्याय को खरीदते रहें ? कानून को लगा कि नरेन्द्र सिंह से गलती हुई है, चुनाव आचार-संहिता के समय नरेन्द्र सिंह से गलती हुई, कानून ने मुझे एरेस्ट किया । मैंने इसके लिए कहीं प्रतिवाद नहीं किया था ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति जी, मैं अंत में कहना चाहता हूं..... (व्यवधान) भईया, बैठने के लिए हमको समय का एकदम ज्ञान है, आप मुझे ज्ञान मत दीजिये, आप अपने नेता को अच्छी सोच दीजिये, सकारात्मक सोच दीजिये जिससे आने वाले कल में आपको भी बिहार की धरती पर मान-सम्मान मिले, सार्थक बहस में हिस्सा लीजिये ।

अंत में मैं वित्त मंत्री जी को दिल से बिहार की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, वर्ष 2016-17 के लिए बिहार राज्य के बजट प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूँ । महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी को कि उन्होंने आजादी के बाद यह पहला सबसे बड़ा बजट बिहार का प्रस्तुत किया है । इसके लिए वे निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं ।

महोदय, अभी भाजपा के नेता नंद किशोर जी केन्द्र सरकार की वाहवाही कर रहे थे लेकिन उन्होंने अभी भारत सरकार का जो बजट आया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की । महोदय, बिहार का बजट 1 लाख 44 हजार करोड़ का आया है और योजना आकार बढ़ा है । अभी नंद किशोर जी ने केन्द्र की सरकार की वाहवाही की लेकिन जो पिछले 10 वर्षों में यहाँ योजना आकार बढ़ा और जो बजट पाँच गुणा बढ़ा है, उसके

पीछे निश्चित रूप से मैं तत्कालीन भारत सरकार, यू0पी0ए0 की सरकार, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसका योगदान मैं मानता हूँ । क्योंकि उस समय की कहावत बहुत प्रचलित है कि नीतीश कुमार जी जाते थे झोला लेकर और बोरा में वहाँ से राशि और सहायता लाते थे। आज उसके विपरीत स्थिति है । जिस 14वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, उस आयोग की अनुशंसाएँ जब तैयार हो रही थीं उस समय बिहार सरकार ने कुछ सुझाव दिये थे। अगर उन सुझावों को माना जाता तो हमारा जो केन्द्रीय कर है, उसमें हमारी हिस्सेदारी और बढ़ती, हमारा योजना आकार और हमारे बजट का आकार भी और बढ़ता। लेकिन इसमें इन्होंने कटौती करने का काम किया और दोषारोपण करते हैं, उस समय काम नहीं हुआ, पिछले बजट भाषण का उद्धरण दे रहे थे, जबकि यही उस समय साथ थे और यही मुख्य बाधक उसमें थे कि उस समय उन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो सका । जब उस समय ये साथ थे तो उन योजनाओं में बाधक बने हुये थे । आज संयोग से उसी सरकार में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जब से साथ हुई है, उसी सरकार ने तेजी से अपना कार्य प्रारम्भ किया है और सात निश्चय के जरिये बिहार की जनता के हितों के लिए पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से अपना बजट प्रस्तुत किया है ।

महोदय, जब चुनाव में हमलोग गये थे तो घोषणा-पत्र के बदले हमलोगों ने सात निश्चय बिहार की जनता के सामने रखा था और उन सात निश्चयों को बिहार की जनता ने एप्रुव किया, उसको इन्डोर्स किया और उसपर अपनी सहमति जतायी, उसपर अपना बहुमत दिया । जिसका परिणाम है कि आज बिहार में इनलोगों को अपनी औकात पता चल गयी और हमें भी बिहार में दो-तिहाई बहुमत से जनता ने यहाँ पर भेजा । महोदय, बिहार की जनता ने जो काम किया, उसके बदले में, बिहार की सरकार ने जो वचन दिया है, यह हमारे नरेन्द्र मोदी का वचन नहीं था जो 25 लाख रूपया अभी तक लोगों के पास अभी आ ही रहा है, अभी एक करोड़ लोगों को रोजगार दे ही रहे हैं ! अभी कल के बजट में इन्होंने एक करोड़ नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का एक प्रस्ताव दिया है जबकि रोजगार का जो प्रस्ताव था उसका कोई पता नहीं है । लेकिन बिहार की सरकार ने हमारे बेरोजगारों के लिए एक हजार रूपया भत्ता दिया है और दो साल तक रोजगार खोजने के लिए अवसर का मौका दिया है कि रोजगार अपना वह उपलब्ध करावे । नौजवानों, महिलाओं और सामाजिक संरचना पर जितना बल दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इसके पहले किसी भी बजट में प्रावधान नहीं था । ...क्रमशः...

श्री अशोक कुमार : (क्रमशः) बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का जाल बिझाने का काम, पोलिटेकनिक, नर्सिंग कॉलेज, पारामेडिकल कॉलेज खोलकर नौजवानों के पलायन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है । यह निश्चित रूप से सराहनीय काम है । जो बाहर में हमारे नौजवान तकनीकी शिक्षा के लिए जाते थे, जो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में भारी राशि देकर बंगलोर, आन्ध्रा, चेन्नई और गुजरात में जाकर अध्ययन करते थे, अब बिहार में उनको शिक्षा लेने का मौका मिलेगा, जो प्रावधान किया गया है। ये जो भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि बजट में कोई प्रावधान नहीं है और ये भूल गये कि यह बजट एक साल के लिए बनता है न कि 5 साल के लिए और चरणवद्ध तरीके से काम हो रहे हैं, आप देखेंगे सभापति महोदय कि बिजली का काम हो या सड़क का काम हो, यह दिखाई पड़ने लगा है । लेकिन वही केन्द्र की योजनायें अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा या इंदिरा आवास की योजना में कटौती नहीं की जाती तो यहां पर योजनायें दिखाई पड़ती । इन योजनाओं में कटौती करके केन्द्र सरकार ने अभी इन योजनाओं में राशि बढ़ा दी है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अभी बिहार में बन्द पड़ी थी और अभी इन्होंने कल के बजट में 19 लाख करोड़ का प्रावधान किया है और वे अपनी पीठ थपाथपा रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक प्रावधान कर दिया है, इतना प्रावधान कर दिया है । जबकि एक साल बिहार के कौस्ट पर उन्होंने राशि बढ़ायी है । एक साल की राशि उन्होंने लगभग रोक दी थी, अब इस बार उसमें बढ़ोत्तरी हुई है । महोदय, इतना भेद–भाव बिहार के साथ हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाकर, अपने आंतरिक श्रोतों को बढ़ाकर जिस तरह के काम प्रारम्भ किया है, वह निश्चित रूप से सराहनिय और स्वागत योग्य है ।

महोदय, अभी आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी के चलते काफी आर्थिक रूप से करों में कमी आयी है । लेकिन उसके बदले में जिस तरह का प्रावधान किया गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा तो उस तरह के प्रावधानों के चलते, उन करों के चलते जो सीधे तौर पर कहीं भी गरीबों को असर नहीं करते, उस तरह के प्रावधान करके श्रोतों को सृजित करने का काम किया गया है । नल से जल का प्रावधान जो कह रहे हैं, वह कोई आज की योजना नहीं है, कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस का शासन होता था, उस समय भी टावर का काम हुआ था लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह जो योजना प्रारम्भ हुई है, वह निश्चित रूप से यह कनसेप्ट नया है और

यह स्वागतयोग्य है । अभी इसमें काम बाकी जरूर है लेकिन इसका चरणवद्ध तरीके से जो एक साल में प्रावधान किया गया है, वह निश्चित रूप से यह राशि एक साल के लिए कम है लेकिन इस राशि को अगले साल से बढ़ाया जायेगा तो दो-तीन साल में यह पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगेगा । उसी तरह ग्रामीण सड़कों और नालियों का निर्माण का काम भी बहुत महत्वकांक्षी योजना है । वह पंचायतों के माध्यम से होता था, जो केन्द्र सरकार वाहवाही लूट रही है, वह तो दिखाई पड़ रहा है कि कितनी उनकी राशि आ रही है । लेकिन जो पंचायतों से काम हुआ, उसमें नाला का काम नहीं होता था और अभी जो काम प्रारम्भ हुआ है , मुझे जानकारी है और मैंने देखा है कि जो सेटलाईट से मैपिंग का काम प्रारम्भ हो गया है और गांव-गांव में जो छूटे हुए टोले एवं बसावट हैं और खास करके उसमें सबसे बड़ा प्रभावित होंगे बिहार के दलित टोले जो कि इन सम्पर्क सड़कों से वंचित हैं । उन्हीं टोलों में ज्यादा कठिनाई है । जहां पर कि दलित बसते हैं और वहां पर सम्पर्क सड़क मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है और यह योजना जो बसावट 250 जनसंख्या वाले गांवों को जोंड़ने का काम किया गया है, वह सीधे तौर पर महादलित और दलित लोगों को प्रभावित करने का काम करेगा ।

महोदय, जो 7 निश्चय किये गये थे, उनको आज जमीन पर उतारने का काम हो रहा है और वह दिखाई पड़ रहा है । आम जनता इस बात को आज भी स्वीकार करती है और इसकी प्रशंसा करती है । विरोधी दल की बात मात्र सिर्फ इतनी है कि एक साल, इन्होंने एक साल में जो काम किये और हमने जो एक साल में काम किये, एक बजट पर कल उनका भी आया और एक बजट तीन दिन पहले मेरा भी आया, दोनों में अन्तर आप देख लीजिए । अगर वे बिहार की इतनी ही चिन्ता करते हैं हमारे नन्दकिशोर जी, सारी योजनायें जितने विकास की बात ये कह रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग में 42हजार करोड़ रू0 दिया, वे अगर इतनी राशि दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं, जो कि यह लम्बी मांग है ? इतनी लम्बी-चौड़ी बात करते हैं कि बिहार को हम कोई पैकेज में कमी नहीं होने दे रहे हैं तो बिहार राज्य का विशेष दर्जा एकमुश्त देने में उनको क्या कठिनाई है ताकि हमलोग बिहार के लिए कोई मांग ही नहीं रखें । अपना जो संसाधन है और जो केन्द्रीय हिस्सा हमारा है, वह मिलता रहे तो उससे हमारे विकास में और सहयोग मिलेगा । महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, आज उस प्रस्ताव का मैं इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री राहुल तिवारी ।

श्री राहुल तिवारी : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट भाषण के समर्थन में खड़ा हूँ । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । मैं सदन में पहली दफे सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आया हूँ, अगर मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाय तो हमें क्षमा करेंगे । हमलोग अभूतपूर्व ढंग से विगत चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी निर्वाचित होकर सदन में आये हैं और विपक्ष के 16वीं विधान सभा के सारे सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ । मैं अपने महागठबंधन के नेताओं ने जो उत्कृष्ट कार्य किये हैं, उसको बताना चाहता हूँ । आज मैं महागठबंधन के सदस्य एवं बिहारी होने पर गर्व महसूस करता हूँ । मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के, देश के, उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर देश में निकले थे, उस समय देश में माहौल खराब हो गया था, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की गई थी तो हमको याद होगा.....

(व्यवधान)

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, नये सदस्य हैं और नये सदस्य जब हाऊस में पहली बार बोलते हैं तो वह मेडेन स्पीच होती है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, टोका-टोकी, डिसटर्ब नहीं किया जाता है ।

श्री राहुल तिवारी : देश में माहौल खराब हो रहा था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि अब क्या होगा तो हमारे बिहार के नेता उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, बिहार में रथ आया तो हमारे माननीय नेता उस रथ को लगाम लगाकर के रोक लगाया और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनको गिरफ्तार किया । मुझे ऐसे नेता पर गर्व है और बिहारी होने के नाते मुझे गर्व है कि जब धर्मनिरपेक्षता तोड़ने की बात आती है तो हमारे लीडर हमलोगों के साथ खड़े रहते हैं । पिछली गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चला रहे थे, विकास की चर्चायें पूरे देश-विदेश में हो रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगे हुए थे, विकास पुरूष की उपाधि उनको मिली थी.....

.....क्रमशः.....

....क्रमशः....

श्री राहुल तिवारी : देश में आम चुनाव होने वाला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेन्द्र मोदी जी का नाम आया कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी होंगे लेकिन उनपर दाग था, उनपर भी गुजरात दंगे से दाग होने के चलते धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमलोगों के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने समझौता का त्याग कर दिया, कुर्सी का त्याग कर दिया और एक अदम्य साहस देश के अन्दर प्रस्तुत किया। इसपर हमलोगों को गर्व है । हमलोगों के माननीया सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जब उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग करके माननीय डॉ0 मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और त्याग की देवी के रूप में अपने आपको देश के अन्दर प्रस्तुत किया । ऐसे गठबंधन के सदस्य के रूप में मैं यहां आया हूँ और मुझे गर्व होता है । बजट के सवाल पर नंद किशोर जी नहीं हैं, बहुत परेशान थे सात निश्चिय को देखकर उनको पसीना आ रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण बातें इन लोगों के दिमाग में आयी कैसे ? कितनी बहुमूल्य बात इसमें लिखी हुई है । युवाओं को बल, बहुत सारे गांव में लड़के मिलते हैं, एक्जामिनेशन के लिए दिल्ली, बंबई जाना पड़ता है तो जो तेज विद्यार्थी होते हैं, उनका एक बार में सेलेक्शन हो जाता है, कई परीक्षा देने के बाद सेलेक्शन होता है और जिनका एक बार में नहीं होता है, उसके लिए बार-बार गरीब मां-बाप से पैसा मांगने में दिक्कत आती है । बार-बार एक्जाम देने जाते हैं और नहीं होता है तो लोग भी बोलते हैं कि हम तुमको पैसा देते हैं और तुम परीक्षा कम्पलिट नहीं कर पाते हो, इसके लिए सरकार युवाओं को महीना में दो साल के लिए एक हजार रूपया मुहैया करा रही है, इससे खूबसूरत चीज युवाओं के लिए कोई हो ही नहीं सकती है । साथ-ही-साथ बैंक से ऋण के लिए जो 12वीं पास करते हैं, उनके लिए तकनीकी ज्ञान के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है एडमिशन के लिए तो बैंक के द्वारा ऋण गारंटी के रूप में बिहार सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठायी है । चार परसेंट के इंटरेस्ट पर बैंक गारंटी के रूप में पैसा उनको मुहैया करायेगी ताकि वे तकनीकी शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सके । दूसरी योजना है घर-घर बिजली, महिलाओं को आरक्षण, घर-घर में नल । नंद किशोर जी बोल रहे थे नल को बजट से हटा दिया गया है, हमको भी यह पता था कि पी0एच0ई0डी0 डिपार्टमेंट में से पंचायत में चार या पांच चापाकल लगाने का प्रावधान था, सार्वजनिक जगह पर पांच तो सार्वजनिक जगह पर जो मजबूत लोग हुआ करते थे, उन्हीं के यहां नल गड़ जाता था, वहां पर लोगों को पानी भरना भी एक समस्या होती थी । हमको भी चयनित करने का मौका मिला, पिछले साल का जो मेरे पहले विधायक थे, वे चयनित नहीं किये, मुझे चयनित करना

पड़ा, काफी समस्या आयी जगह को लेकर । उस पंचायत में 9 गांव हैं और मुझे पांच ही चापाकल देना है, बहुत मुश्किल था । योजना को समाप्त किया गया, इसके जगह पर खूबसूरत योजना है कि हम घर-घर नल से पानी पहुंचायेंगे, इतनी खूबसूरत योजना गरीबों के लिए है । नंद किशोर जी बजट पर बोल रहे थे कि व्यक्ति के द्वारा बजट बनाया गया है, वे पुराने सदस्य हैं, बजट व्यक्ति का नहीं होता है, सरकार का बजट होता है । मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि बजट सरकार बनाती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है लगता है कि ये भारत के एजेंट हैं । केन्द्र सरकार योजना के लिए पैसा देती है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि किस राज्य को कितना अधिकार है, केन्द्र को कितना अधिकार है और उसी अधिकार से केन्द्र पैसा देती है, कोई एहसान नहीं करती है । यह मेरा अधिकार है, यह मेरा लेना कर्त्तव्य है और केन्द्र सरकार को जितनी सर्विस टैक्स होती है, सेल्स टैक्स होती है, बिहार के लोग भी टैक्स देते हैं, जिसके चलते केन्द्र में पैसा आता है । इतनी खूबसूरत योजना का मैं समर्थन करता हूँ, इस योजना में जो विशेषकर वंचित समाज हैं, जो मूलभूत सुविधायें से वंचित हैं, उनको इसमें प्रथम पृष्ठ में रखा गया है । यह एक सराहनीय कदम है । मैं मानता हूँ कि इस गठबंधन की सरकार, हमारे विकासशील मुख्यमंत्री और युवा हमारे उप मुख्यमंत्री, अनुभवी वित्त मंत्री मिला है सरकार को कि वे बेहतर से चलायेंगे और भारत में बिहार अपना नाम रोशन करेगा ।

धन्यवाद ।

सभापति : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी, दो मिनट समय है आपके लिए ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, आज बिहार का बजट आया है, महोदय, मैं जहां से जीतकर आता हूँ, दो बार-तीन बार मैंने बोला किसी को 52 वर्ष, किसी को 55 वर्ष , किसी को 15 साल, किसी को 11 साल और कई माननीय सदस्यों को दस-दस बार जीतने का मौका मिला है, हमलोग जीतकर आये हैं दूसरी-तीसरी बार । चापाकल से पानी बंद कर दिया सरकार ने, अब घर-घर में नल दीजियेगा, हमारे यहां आगे पीने का पानी नहीं है, मैं यह सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ । आज भी पीने का पानी नहीं है और वहां के पशु और इन्सान दोनों दो घूंट पानी के लिए मुहताज हैं और अब आपटंकी लगाइयेगा, कब लगाइयेगा, तब तक बहुत लोग मर जायेंगे,मै आज यहां तसला लेकर आया था पानी मांगने के लिए, आपका मार्शल तसला ले लिया, सोचा कि आज सदनके माध्यम से तसले में पानी ले जायेंगे, चैनारी के लोगों को पानी पीने के लिए नौहट्टा, रोहतास, चैनारी, शिवसागर, तिलौथ टू सासाराम और बगल में कैमूर का जिला है, जहां रामपुर, भगवानपुर,अधौरा, चैनपुर, चांद, 11 से 12 प्रखंडों में पानी का लेयर

उठ चुका है । कौन सा नियम और कानून की बात हो रही है सदन में, हम सदन के माध्यम से जानना चाहते हैं । नियति है सरकार में, आप रहियेगा, कल नहीं रहियेगा, हम भी आज एम0एल0ए0 हैं, कल नहीं रहेंगे लेकिन काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है । मुझे लज्जा के साथ, शर्म के साथ, मन नहीं करता है बोलने का लेकिन आश्चर्य है कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । आज पशु और इन्सान दोनों एक ही घाट पर गंदा पानी पी रहे हैं । हम बिजली नहीं देंगे, हमारे यहां तीन सौ, चार सौ गांव ऐसे हैं, जिसने बिजली आजतक नहीं देखा है और बिजली मंत्री जी कह रहे थे कि हम बिजली देंगे, कब पहुंचेगा बिजली । बगल में गुप्ता धाम है, वहां पर इन्सान और जानवर को जानने का रास्ता नहीं है । पहाड़ पर मैं 18 किलोमीटर चढ़ा और 18 किलोमीटर पैदल लौटा गुप्ता धाम । लोगदेवघर के बाद लाखों-लाख गुप्ता धाम आते हैं, शिव ने भस्मासुर को अमरतत्व का वरदान दिया था । व्यवधान ... सरकार में हम भी रहे थे, आप भी रहे थे अशोक बाबू, आप घबराइए नहीं और मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि सड़कों की वही हालत बद से बदतर, पीने के पानी का बद से बदतर स्थिति सिर्फ सदन के माध्यम से बजट का सिर्फ बिहार में पांच प्रतिशत् लोगों को सिर्फ पीने का पानी मुहैया करा दे सरकार, हम सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं ।

सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हम समाप्त ही कर रहे हैं लेकिन सरकार पीने का पानी दे, नहीं तो पशु और इन्सान दोनों मरेगा और उसकाप्रायश्चित सरकार को करना पड़ेगा, हम एम0एल0ए0 हैं, हमलोगों को चपरासी नहीं बनाइए कि हम एक चापाकल भी अनुशंसा नहीं कर सकते, वह भी आपने बंद कर दिया । नौकरशाहों से सिर्फ राज्य नहीं चलेगा, हम जन-प्रतिनिधि हैं, हम जीतेंगें, हारेंगे लेकिन क्यालोकतंत्र में नौकशाहों से राज्य चलेगा?जन-प्रतिनिधि को बौना कर दिया जायेगा तो जनतंत्र बचेगा नहीं ।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी । अब आप बैठ जाइए ।

टर्न-18/शंभु/01.03.16

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : महोदय, वित्तीय वर्ष-2016-17 के बजट में सामान्य विमर्श में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं कोटि-कोटि नमन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी कृपा से पहली बार मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है। हम उनको कोटि-कोटि नमन करना चाहते हैं। इस बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब ने जो पेश किया है। हम उसके समर्थन में सामान्य रूप से अपनी बात को रखना चाहते हैं। महोदय, जो बजट सामने आया है, वह बजट काफी कारगर है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो पास हुआ है मुझे पूरा भरोसा है अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर कि जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उनके कथनी और करनी कभी फेल नहीं हुआ है, हमेशा मेल होने का काम हुआ है। मैं जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के वरिष्ठ नेता बोलकर अभी जो चले गये वे बार-बार कहते थे कि बजट में कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे नेता की नीति और नीयत दोनों इतने अच्छे और सुंदर हैं कि जो प्रस्तुत करते हैं, जो बोलते हैं उसे पहले करके दिखाने का काम करते हैं। जो सात निश्चय हुआ है - सातों निश्चय अपने आप में बेमिशाल है। युवाओं को जो रोजगार देने की बात है कि एक साल में एक-एक हजार रूपया देने का काम करेंगे। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए घोषणा किया कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे जो बच्चे गरीब लोग हैं, जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे। सात निश्चय में एक निश्चय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया जो बिहार के नौकरी में हमारे बिहार की जो छात्रा हैं, महिलाएं हैं, बेटी है उसको 35 परसेंट आरक्षण देने का फैसला यह स्पष्ट कर देने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं उनसे जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे कि इसलिए जानना चाहते हैं कि सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। लोक सभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आयेंगे, उन्होंने कहा था कि कालाधन 90 दिन के अंदर लायेंगे और 15 से 20 लाख रूपया हिन्दुस्तानी के खाता में डालने का काम करेंगे, लेकिन आज तक 15 से 20 हजार रूपया बोहनी तक कराने का काम नहीं किये। हम जवाब चाहते हैं उनसे। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला बल्कि जो युवा अपनी नौकरी की बात उठाता है, जो हक हुकूक की आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोह के रूप में उसपर केस करके उसको जेल में भेजने का काम किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या युवा इस देश का नागरिक नहीं है।

आप कहते कुछ हैं और करने के समय पिछड़ जाते है। आज कन्हैया ने जो बोला, आज उसपर गर्व है कि वह बिहार का बेटा है और बिहार कभी राष्ट्रद्रोह के लिए नहीं लड़ सकता है, बिहार का बेटा कभी नकारा नहीं हो सकता है, इस देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। मुझे गौरव है इस बात पर बिहार वीरों का बिहार रहा है, यह बिहार डपोरशंखियों और कायरों का नहीं रहा है। जिसका नतीजा है कि इस विधान सभा के चुनाव में बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव के झंडा को फहराने का काम किया, उनको तिलक लगाने का काम किया और बाहर के लोगों को दिल्ली भगाने का काम किया, यह बिहार की जनता ने साबित करने का काम किया है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप जो कहिये वह करके दिखाइये। आपने कहा था कि किसानों के समर्थन मूल्य फसल के समर्थन मूल्य का 50 परसेंट बढ़ाकर देने का काम करेंगे। आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि हम- हमारा चार सैनिक का सिर जायेगा तो हम 14 काटकर लायेंगे, लेकिन आपके सामने अत्याचार हो रहा है और आप उसपर घ्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया को और हार्दिक पटेल को देशद्रोह में फंसाकर खड़ा करने का काम किया जेल में, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है और हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो नारा लगा रहा है उसपर राष्ट्रद्रोह का केस क्यों नहीं हो रहा है ? हम यह जानना चाहते हैं विपक्ष के लोगों से। हम जानना चाहते हैं माननीय महोदय कि जो बजट पर काम हुआ, बजट के सवाल पर कृषि के सवाल पर हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 में कृषि रोड मैप बनाने का काम किया और आज तक मैं समझता हूँ कि कोई अगर किसान हो बिहार का ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा जिसके घर में हंसुआ, खुर्पी, सेक्शन पाइप डिलेवरी पाइप और ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर तक, डीजल मशीन तक हर किसान के घर में सबसिडी पर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और इतना ही नहीं कराया। हम यह भी करना चाहते हैं कि लोग बार-बार केवल छींटाकसी करते हैं, काम में वे लोग विश्वास नहीं रखते हैं। ग्रामीण कार्य विकास के सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे तो सौ प्रतिशत राशि आती थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, कांग्रेस के शासन में सौ प्रतिशत राशि आती थी और आज कौन सी मुसीबत आ गयी केन्द्र सरकार को कि कह रही है कि 60 परसेंट हम देंगे और 40 परसेंट बिहार सरकार देगी यह कौन सी मुसीबत है। हम जानना चाहते हैं लोगों से । हम और कहना चाहते हैं कि हमारा जिला नक्सल प्रभावित है रोहतास जिला वहां एक योजना चलती थी आइ0एफ0पी0 आज उस योजना को बंद कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना है। मेरे क्षेत्र में 10 ऐसे सड़क

हैं जो 26 कि0मी0, 10 कि0मी0, 12 कि0मी0 सड़क है, जो केन्द्र सरकार की एजेंसी एन0बी0सी0सी0 ने काम किया और आज तक उस कार्य को पूरा नहीं कराया। सात वर्षों से सड़क ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम सदन से मांग करते हैं कि वह सड़क जो बना है, जो केन्द्र सरकार की एजेंसी एन0बी0सी0सी0 काम कर रही है उसपर संज्ञान लेते हुए तत्काल उस सड़क को बनाने का काम किया जाय। हम सड़क की सूची देने के लिए भी तैयार हैं। माननीय महोदय, कहना चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए हमारी आनेवाली पीढ़ी के लिए- भरतीय जनता पार्टी के लोग लोक सभा चुनाव से पहले बिहार में ट्रेन का चक्का जाम करने का काम किया था और जब नीतीश सरकार बन गयी तब सरकार बनने के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भूल गये। कल जो बजट आया है कि उस बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात नहीं है। हम आग्रह करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें।

महोदय, जंगल राज की बात करते हैं, हमारे विपक्ष के नेता भाषण कर रहे थे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी शोरगुल करके भाषण में बोल रहे थे जंगल राज- हम पूछना चाहते हैं विपक्ष के लोगों से कि किस जंगल राज की बात करते है? मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के हाथ में जब तक बिहार का कमान रहेगा, बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज कायम रहेगा, कानून का राज कायम रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता हैं। हम पूछना चाहते हैं बी0जे0पी0 के लोगों से कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रालोसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छाती तोड़ देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि यह किस तरह की बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने की बात करते हैं और किस जंगह राज की बात करते हैं।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि लेकिन हमलोगों के जैसे नौजवान से कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा चाहेंगे और आपने जो मुझे समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सीताराम यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ 1 2015 के अंतिम महीने में जनता की कृपा से महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार न्याय के साथ विकास के परचम को लहराने का आश्वासन मिला औार उसका बजट और चुनाव में किए गए वायदे के आधार पर आवाम के हालात को बदलने के लिए जो सरकार माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें हमारे गांव के गरीब किसान मजदूरों की भलाई निहित है । इन सारी बातों को इन्होंने समेटने का काम किया है 1 महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय वित्त मंत्री और सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूॅ ,साधुवाद देता हूँ 1 महोदय, ये हमारी सरकार 7 निश्चय जो लिया है 7 सूत्री जिसमें सभी बातों पर ध्यान दिया गया है जैसे हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि सभी तरह की भलाई आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर को बिजली , हर घर में नल का जल ,घर तक पक्की गली नालियॉ शौचालय । आज हम महोदय, मधुवनी से आए हैं साढ़े तीन घंटा में, हम मधुबनी से महोदय यहॉ पहुंचे हैं । यह महागठबंधन की सरकार का निश्चय दर्शाता है कि साढ़े तीन घंटा में 225 कि0मी0 की दूरी हमने पटना तक तय किया है 1 परसों रात महोदय, हम जा रहे थे..

(व्यवधान)

क्या दिक्कत हो रहा है । जरा सुनिये तो । थोड़ा सा धैर्य से सुनिये तो । महोदय, हम जा रहे थे चारों तरफ गांव रात में शहर की तरह बिजली से चकाचौंध ,चारों तरफ बिजली जगमग जगमग कर रही है । कोई सदस्य अपने कलेजे पर हाथ रख कर आप गांव में जाते होंगे कहां नहीं बिजली है आप बताईये । हर घर में बिजली हर गांव में पक्की सड़क , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ,मैं धन्यवाद देता हूँ वाजपेयी जी को जिन्होंने बढ़िया स्कीम चलायी थी, 100 में 100 और आपने काट कर 100 में 40 किया 60 किया और जोर से बोल रहे हैं कि विकास नहीं और टोका टोकी कर रहे हैं आपको सुनने की हिम्मत नहीं है, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं । आप अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं इससे क्या होगा 9 जनता जानती है । सब कुछ जानती है । आप धोखे से ठग कर वोट ले लिया था पार्लियामेंट के चुनाव में और आ गया सही वक्त लोगों ने निर्णय करके एक कोना में आपको समेट कर रख दिया है । हमारे लालू जी कहे थे कि 6 महीना हम समय देंगे और 6 महीना तक हम इंतजार करेंगे । पहली विधान सभा की कार्यवाही हो रही है ,और आप एक घंटा एक दिन नहीं जाते हैं बाहर में फोटो खिंचवाते

हैं कैमरा मैन को अखबार वाले को बुलाकर तख्ती लटकाते हैं क्या मिलने वाला है 5 वर्ष तक इंतजार करिये मेरे मित्र । जनता का निर्णय असली निर्णय है,समेट कर एक कोना में रख दिया ,श।र्म होनी चाहिए । जनता के निर्णय को नहीं मानने के लिए तैयार हैं और गाल बजाते हैं । एक कोने में सिमट गए ,सारे जगह हमलोग बैठे हुए हैं हमारा वहाँ होना चाहिए था । जोर से मत बोलिये । और श।र्म करिये जनता के निर्णय को, उनके आदेश को शिरोधार्य करिये । आप उनका जो निर्णय हुआ है उसको शि।रोधार्य करिये । 100 में 40 करते हैं, 60 करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना आप उसको काट के बना दिए हैं पंडित दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना , नाम आपका और पैसा कहते हैं बिहार वाले देंगे । पंडित दीन दयाल उपाध्याय का नाम दिया गया और राजीव गांधी का नाम हटा , जब राजीव गांधी का नाम था तो 100 में 100 पैसा केंद्र का लगता था लेकिन आज 60-40 कर दिए हैं ,नाम ले रहे हैं नाम अपना। माल महाराज का और मिर्जा खेले होली ,यह नहीं चलेगा । दोहरी नीति और दोगली नीति नहीं चलेगी । जनता जानती है , हम जानते हैं ,सब लोग जानते हैं । आज आप आते हो बिहार में एक तरफ हेलीकॉप्टर हमेशा मंडराता रहता था,बिजली आयी,बिजली आयी । जनता जानती थी ये चिढ़ा रहा है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं । आप तो राम राम हरे राम जपने वाले हैं , आपको तो पण्डा पुजारी के पास ,मंदिर में जाना चाहिए । विकास से आपको क्या वास्ता 9. विकास का मतलब- रोटी कपड़ा और मकान होता है । विकास का मतलब शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सड़क ,बिजली होती है । विकास का मतलब हरे कृष्णा हरे राम नहीं होता है । कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनायेंगे । कहाँ मंदिर बनेगा । मंदिर मस्जिद बनाना पंडा पुजारी का काम है । मौलवी मौलाना का काम है । ये राजनीति करने वाले राजनीति की रोटी मंदिर पर सेंकते हो आप और आकर हाउस के अंदर जहाँ इतने कलाकार लोग सभी लोग जानते हैं ,आपको शर्म होनी चाहिए ,निर्णय लेना चाहिए । आपमें बदलाव आना चाहिए । नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार मैं पूछना चाहता हूँ कि आज गांव में पासवान जाति की महिला मुखिया होती है । रविदास जाति की महिला मुखिया होती है, हमारे मुश।हर भाई के घर की महिला मुखिया होती है और आप जीतन राम मांझी को बना करके नीतीश जी ने मौका दिया और धोखे में जाल में उनको फंसा करके आपने उनको गिराया और प्रचार करने जाते हैं कि नीतीश कुमार ने हटा दिया । आप अपने जाल पास में नाग पास में बांधना चाहते थे आप कभी नहीं चाहते थे कि गरीब का बेटा एम0एल0ए0 बने , मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री बने ,आप पैसों की राजनीति करने वाले हम जहाँ से महोदय जीतकर आए हैं हमारे खिलाफ में ये राम के नाम के ढोंगी लोग दारु बांटते थे ,पैसा बांटते थे ,क्या यही है राम का आचरण । राम का आचरण दारु बांटना और मुर्गा का

टांग बांटना ,पोलीथीन में मुर्गा के टांग का मांग और दारु हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि महोदय, इसके लिए आप कमिटी बनाईये , इसकी जॉच होनी चाहिए ,जनता के बीच में इसकी जांच होनी चाहिए ,ये राम का नाम लेते हैं ,मुर्गा का टांग बांटते हैं ,दारु बांटते हैं और पैसा बांटते हैं । पैसे के बल पर जीत कर आते हैं ,यहां शान और शेखी बघारते हैं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें 1

श्री सीता राम यादव : महोदय, एक चीज कहना चाहता हूँ कि शान और शेखी जनता सब कुछ जानती है इसलिए इनको कोने में लाकर बैठा दिया । अब आप आत्म चिंतन करिये, मंथन करिये और गिरेबान में झांकिये और जनता के बीच में जाईये और हाथ जोड़िये, माफी मांगिये तब जाकर कहीं विस्तार होगा, नहीं तो इसमें से भी आप घट जायेंगे । महोदय, आपका आदेश होता है आपने जो हमें समय दिया ,मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके आदेश का अक्षरश: पालन करता हूँ और बैठ जाना चाहता हूँ । जयहिंद ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श कल दिनॉक 2 मार्च 2016 को भी जारी रहेगा ।

आज दिनॉक 1 मार्च 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 8 है सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों में भेज दिया जाय ।

(सदन सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनॉक 2 मार्च 2016 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।